छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 200 ■ अम्बिकापुर, रविवार 02 अगस्त 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

आतंकी हमला मारे गए छत्तीसगढ़ के मजदूरों के परिवार को 20-20 लाख की मदद

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में श्रमिकों की मौत पर दुख जताया है. उन्?होंने कायराना हमले में जान गंवाने वाले सक्ती जिले के दीपक रात्रे और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निवासी भूपेंद्र भैना के निधन पर शोक व्यक्त किया है.साथ ही उनके परिवारों को 20-20 लाख रुपये की मदद करने का भी ऐलान किया गया है. आइए, सबसे पहले जानते हैं आतंकी हमले में मारे गए मजदूर कौन थे?

घर में इकलौता कमाने वाला था दीपक

दरअसल, छत्तीसगढ़ के गांवों से गरीबी के कारण रोजगार की तलाश में दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना बेहतर भविष्य का सपना लेकर जम्मू-कश्मीर पहुंचे थे. जहां केलम क्षेत्र में स्थित ईंट-भट्ठे पर आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्?या कर दी. अब सिर्फ उनके शव ही घर लौटेंगे. मालखरौदा पुलिस थाना इलाके के बुंदेली गांव के रहने वाले चाचा हलधर रात्रे ने बताया कि दीपक रात्रे (24) अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था.

दीपक की शादी कुछ साल पहले हुई थी, उसके परिवार में उसकी पत्नी और चार महीने का बेटा है. बेहतर भविष्य की उम्मीद में सात-आठ महीने पहले वह अपनी पत्नी के साथ जम्मू-कश्मीर गया था.दीपक के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, उसका छोटा भाई दिव्यांग है. दीपक की मौत के बाद मां और भाई का रो-रोकर बुरा हाल है.

तीन महीने पहले मजदूरी करने गए थे भूपेंद्र भैना

आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दूसरे मजदूर भूपेंद्र भैना सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छुइया गांव के रहने वाले थे. 28 साल के भैना 3-4 महीने पहले पत्नी के साथ ईंट-भट्टे पर काम करने के लिए जम्मू-कश्मीर में गए थे. उनका चार साल का बेटे, मां और नाबालिग बहन गांव में ही रह रही थी. सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के अनुसार उनके माता-पिता और छोटा भाई हिमाचल प्रदेश में ईंट-भट्टे पर मजदूरी करते हैं.

सरकार परिवारों के साथ खड़ी-मुख्यमंत्री साय ने इस जघन्य और अमानवीय आतंकी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है और ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं. उन्?होंने कहा कि? इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है. मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की कि राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.इसके अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी. यह राशि जिला प्रशासन की ओर से दी जाने वाली 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता से अलग होगी.

युवा कांग्रेस चुनाव में बड़ा उलटफेर-आदित्य भगत का नामांकन रद्द ,शैलेंद्र बंजारे और सत्येंद्र चेलक के बीच सीधी टक्कर

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय युवा कांग्रेस (ढ्ढङ्घष्ट) ने स्क्रूटनी के बाद वैध उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत का नामांकन आयु सीमा पूरी नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद अब प्रदेश चुनाव मैदान में रह गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कुल 19 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी के दौरान आदित्य भगत को अपात्र घोषित कर दिया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के नियमों के मुताबिक 28 मई 1990 के बाद जन्मे उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसी नियम के आधार पर उनका नामांकन रद्द किया गया।

अध्यक्ष पद के लिए 17 उम्मीदवार

मुकाबला दो गुटों के बीच सिमटने की चर्चा-नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस के भीतर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। संगठन के अंदर चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद की लड़ाई अब मुख्य रूप से शैलेंद्र बंजारे और सत्येंद्र चेलक के बीच सिमट गई है। बताया जा रहा है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व मंत्री रुद्र गुरु का समर्थन शैलेंद्र बंजारे को मिल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन सत्येंद्र चेलक के पक्ष में माना जा रहा है।

सिर्फ अध्यक्ष नहीं, कई पदों पर होंगे चुनाव-युवा कांग्रेस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 53 प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई पदों के लिए भी चुनाव होना है। मतदान प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

अध्यक्ष पद के 17 उम्मीदवार-स्क्रूटनी के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सत्येंद्र चेलक, शैलेंद्र बंजारे, विनोद कश्यप (भक्कू), भावेंद्र गंगोत्री, दीक्षा पांडे, जसमीत शर्मा (सोनू शर्मा), कपिल कांत नाग, मानव देशमुख, मृदुला भास्कर, परमीत बग्गा (हनी बग्गा), प्रशांत बोकड़े, प्रीतिका विश्वकर्मा, प्रीति वैष्णव, सागर बाघमारे, सजल चंद्राकर, शालिनी रामटेके और सोनिका पोर्ते चुनाव मैदान में हैं।

संगठन से ज्यादा सियासी ताकत की परीक्षा-युवा कांग्रेस का यह चुनाव केवल संगठन का नया अध्यक्ष चुनने तक सीमित नहीं माना जा रहा। कांग्रेस के भीतर इसे अलग-अलग नेताओं के प्रभाव और शक्ति संतुलन की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का नतीजा आने वाले समय में युवा कांग्रेस के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

नए न्यायालय भवन के भूमिपूजन की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। राज्य अधिवक्ता परिषद्, छत्तीसगढ़ के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अंबिकापुर स्थित वर्तमान न्यायालय परिसर में प्रस्तावित नवीन न्यायालय भवन का भूमिपूजन करने का आग्रह किया है।

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि, अंबिकापुर में नए न्यायालय भवन के निर्माण की मंजूरी और राशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान न्यायालय भवन जर्जर स्थिति में है, इसके कारण न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों को न्यायिक कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरगुजा संभाग के अधिवक्ताओं की ओर से मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वे यथाशीघ्र अपनी उपस्थिति में नवीन न्यायालय भवन की आधारशिला रखें। परिषद का मानना है कि यह उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि होगी और सरगुजा अंचल इससे गौरवान्वित होगा। पत्र की प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म के फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुई सख्त

लाइसेंसी बंदूक जप्त, संपत्ति कुर्की और अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भफौली निवासी तरुण जायसवाल के विरूद्ध नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में प्रकरण दर्ज है। कई बार दबिश के बाद भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ऐसे में सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इधर घटना के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हेने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपी के लाइसेंसी बंदूक को जब्त किया है, वहीं संपत्ति की पड़ताल कर रही है। मामले में पहले ग्रामीणों की पहल पर पीड़िता अपने स्वजन के साथ कोतवाली थाना पहुंची थी। हाल में पुनः ग्रामीणों का जत्था थाने पहुंचकर जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर हल्ला बोला था। प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने भी पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। इधर जनाक्रोश के बीच आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा है। पीड़िता के थाने पहुंचते ही यदि दबिश दी जाती तो आरोपी को भागने का मौका नहीं मिलता, इसे लेकर भी लोगों में नाराजगी है। थाना कोतवाली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में धारा 65(1) बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत मामला दर्ज है।

दोनों मामले में इस नंबर पर दें सूचना

पुलिस ने आमजन से अपील की है, यदि किसी को आरोपी के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस अधीक्षक को 94791-93501, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को 94791-93502, पुलिस नियंत्रण कक्ष में 94791-93599 पर सूचित करें। सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसे जल्द गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।

एसएसपी ने की 5000 इनाम की घोषणा

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने तत्काल विशेष पुलिस टीम का गठन किया है। आरोपी की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सार्थक सूचना देने वाले को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा भी की गई है। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखने की बता कही गई है।

शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा-आरोपी के नाम पर पूर्व में 12 बोर डीबीएल बंदूक मय लाइसेंस जारी किया गया था। आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण विवेचना प्रभावित हो सकती है, इसे देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली के प्रतिवेदन पर लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजी गई थी। अग्रिम कार्रवाई के तहत कोतवाली पुलिस टीम ने आरोपी के परिजनों से उक्त लाइसेंसी बंदूक को जप्त कर लिया है।

आरोपी के संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू-पुलिस टीम द्वारा मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग से आरोपी तरुण जायसवाल, निवासी ग्राम भफौली के चल व अचल संपत्ति की जानकारी ले रही है। साथ ही ग्राम भफौली में आरोपी के द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि का मौके पर सत्यापन कराकर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।

शरण देने वालों पर भी होगी कार्रवाई-पुलिस टीम आरोपी के संभावित सभी ठिकानों पर लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। आरोपी को शरण देने या मदद करने वाले व्यक्तियों पर भी पुलिस की निगाह है और उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दे चुकी है। पूर्व में भी पुलिस जघन्य मामलों में आरोपी को शरण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है।

ज्वेलरी चोरी के आरोपी का पुष्ट सुराग बताने वाले को मिलेगा 5000 ईनाम

सरगुजा जिला के थाना सीतापुर क्षेत्र में ज्वेलरी का बैग लेकर फरार हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने 5,000 रुपये के ईनाम की घोषणा की है। बता दें कि, अरुण देव सोनी पिता स्व. कांशीराम सोनी निवासी सीतापुर के द्वारा श्री काशी विश्वनाथ ज्वेलरी दुकान का संचालन किया जाता है। वे 26 जुलाई को सुबह लगभग 11.30 बजे अपनी स्कूटी वाहन के सामने सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग रखकर दुकान का शटर खोल रहे थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति स्कूटी के सामने रखा बैग लेकर फरार हो गया। बैग में लगभग एक करोड़ रुपये का सोने-चांदी के सामान रखा था। मामले में थाना सीतापुर में धारा 303(2) बी.एन.एस. का मामला पुलिस ने पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। आरोपी की पतासाजी के हरसंभव प्रयास के बाद भी पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। व्यापारियों ने एक दिन पहले शुक्रवार को ज्वेलरी चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में शहर बंद करके करीब 5 घंटे चक्काजाम किया था। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एक सप्ताह का समय मांगते हुए कहा कि पुलिस टीम आरोपी के पतासाजी में निरंतर लगी है। बड़ी घटना के बाद पुलिस अब तक सैकड़ों सीसीटीव्ही फुटेज खंगाल चुकी है, लेकिन शातिर आरोपी तक पहुंच पाने में विफल रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति अज्ञात आरोपी के संबंध में ऐसी ठोस जानकारी देगा, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके, उसे 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। पुरस्कार वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक सरगुजा का होगा।

पैरामेडिकल कोर्स में शुरू नहीं हुआ दाखिला, छात्रों को सत्र गंवाने का डर

मेडिकल कॉलेज की 60 सीटों पर दाखिला अटका, नेता प्रतिपक्ष ने की कलेक्टर से चर्चा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रस्तावित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने में हो रही देरी से पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। समय रहते प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो विद्यार्थियों को इस शैक्षणिक सत्र का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मामले को लेकर नगर निगम अंबिकापुर के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कलेक्टर अजीत वसंत से चर्चा कर विद्यार्थियों के हित में जल्द पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में देरी का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ेगा। इसलिए प्रक्रिया जल्द शुरू होना जरूरी है, ताकि छात्र-छात्राओं को इसी सत्र में प्रवेश मिल सके और उनका एक वर्ष खराब न हो। कलेक्टर ने चर्चा के दौरान शफी अहदम से कहा कि मेडिकल कॉलेज के डीन को आवश्यक दस्तावेज और संबंधित पत्र के साथ सोमवार को उनके पास भेजें। मामले की पूरी जानकारी और दस्तावेज देखने के बाद विद्यार्थियों के हित में आवश्यक पहल की जाएगी। इसके बाद सोमवार को मेडिकल कॉलेज के डीन की कलेक्टर से मुलाकात प्रस्तावित है। उम्मीद है कि इसके बाद प्रवेश संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों को इसी सत्र में दाखिला दिलाने की दिशा में आवश्यक पहल होगी।

आयुष ने नियम एवं शर्तें नहीं की जारी

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मेश्राम ने बताया कि आयुष विश्वविद्यालय की ओर से पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक नियम एवं शर्तें अभी तक जारी नहीं की गई हैं। प्रवेश संबंधी नियम-शर्तें जारी नहीं होने के कारण कॉलेज स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। ऐसे में क्षेत्र के विद्यार्थियों को मेडिकल क्षेत्र में रोजगारपरक शिक्षा हासिल करने स्थानीय अवसर मिलने की जगी उम्मीद को झटका न लगे, इस पर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू हो, ताकि विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में दाखिला मिल सके। प्रवेश में और देरी होने पर छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ उनका एक वर्ष भी खराब हो सकता है। ऐसे में विद्यार्थियों के हित में संबंधित स्तर पर जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुरू कराने की जरूरत है।

आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म, अपराधी का पुतला दहन करके सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के आह्वान पर, सरगुजा जिले में नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म के विरोध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन कर आरोपी का पुतला दहन किया गया। आरोप है कि, कांग्रेस के परसा मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच एवं उनके परिजनों द्वारा नाबालिक के परिवार के लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर मामले को शांत कर समझौता करने का भी निरंतर दबाव बनाया गया, जो काफी निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर स्वजन ने मामले को गंभीरता से लेकर इसे अस्वीकार किया और आरोपी के विरूद्ध पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। नाबालिग आदिवासी बालिका के साथ हुए इस अमानवीय घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश है। भाजयुमो समलाया मंडल एवं परसा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोपी तरुण जायसवाल के कृत्य के विरोध में उसका पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। पुतला दहन के दौरान जिला महामंत्री विनोद हर्ष, महामंत्री द्वय अरुणा सिंह, जन्मेजय मिश्रा, रवि विश्वकर्मा, समीर श्रीवास्तव, अनीश सिंह, अविनाश मंडल, मंडल अध्यक्ष आयुष दुबे, रोहन मंडल एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बाल गंगाधर तिलक को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन बलरामपुर में जिला कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बलरामपुर के संयुक्त तत्वावधान में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने लोकमान्य तिलक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके आदर्शों त्याग बलिदान और राष्ट्रहित में दिए गए अमूल्य योगदान को स्मरण किया। वक्ताओं ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने देशवासियों में स्वतंत्रता की चेतना जगाने का ऐतिहासिक कार्य किया और उनका जीवन आज भी समाज व युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समीर सिंह देव, जिला कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत विश्वास, संजीत चौबे, ब्लॉक उपाध्यक्ष अरुण दास, शोएब सिद्दीकी, कृपाशंकर राम, जयराम सिंह, प्रशांत बाला, विनोद मेहता, आशिम विश्वास, अरमान अली, फेंकू पाल, कीर्तन, राजेश गुप्ता, रीना कुजूर, पार्षद बिर्जिनिया केरकेट्टा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों के लिए न्यू टैलेंट फुटबॉल प्रोत्साहन कप आज से

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। जिला फुटबॉल संघ सूरजपुर द्वारा विशेष रूप से स्कूली विद्यार्थियों में फुटबॉल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने एवं खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यू टैलेंट फुटबॉल प्रोत्साहन कप का आयोजन 2 से 15 अगस्त तक एकता स्टेडियम विश्रामपुर में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता केवल विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना, उनमें अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना है।

जिला फुटबॉल संघ ने क्षेत्र के सभी शासकीय, अशासकीय एवं केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों से आग्रह किया है कि वे अपने विद्यालय की फुटबॉल टीमों को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु नामांकित करें तथा विद्यार्थियों को इस आयोजन में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करें।

आयोजन समिति के राजेश जैन ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों एवं खिलाड़ियों को ट्रॉफी, पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण योजना में

बैंक सखी ने बीपीएम व पीआरपी पर लगाए गंभीर आरोप

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित महिला सशक्तिकरण और स्व-सहायता समूहों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत सिलफिली क्षेत्र की राधा महिला कलस्टर संगठन की बैंक सखी अर्चना मंडल एवं संगठन की कई महिलाओं ने कलेक्टर को कई लिखित शिकायतें सौंपते हुए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और पीआरपी पर गंभीर अनियमितताओं, पक्षपात, मानदेय में कटौती, वित्तीय गड़बड़ियों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा योजनाओं के संचालन में मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। लगातार सामने आई शिकायतों ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों में महिलाओं ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। बैंक सखी अर्चना मंडल ने आवेदन में आरोप लगाया है कि वर्ष 2024-25 के दौरान नियमित रूप से कार्य करने के बावजूद उनका मानदेय काट दिया गया। उनका आरोप है कि बार-बार अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उल्टा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। महिला क्लस्टर संगठन की सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बैठकों में लोकतांत्रिक

प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव बिना सदस्यों की सहमति के पारित कर दिए जाते हैं। विरोध करने वाली महिलाओं की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और निर्णय पहले से तय कर लिए जाते हैं। महिलाओं का कहना है कि संगठन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। शिकायतों में व्हीपीआरपी सर्वे को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कई पात्र परिवारों का सर्वे नहीं किया गया, जबकि कुछ अपात्र लोगों के नाम जोड़े गए। सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई मामलों में बिना वास्तविक सत्यापन के कार्य पूर्ण दिखा दिया गया। आरोप यह भी लगाया गया है कि सर्वे के नाम पर राशि की मांग की गई तथा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर महिलाओं को भ्रमित किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अनियमितताओं का विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्हें बैठकों में अपमानित किया गया तथा शिकायत वापस लेने के लिए मानसिक दबाव बनाया गया। कुछ महिलाओं ने अधिकारियों के व्यवहार को महिला सम्मान के विपरीत बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं होगी और जिम्मेदार अधिकारी मनमानी करेंगे, तो इसका सीधा नुकसान ग्रामीण महिलाओं और योजना की विश्वसनीयता को होगा। बैंक सखी अर्चना मंडल ने यह भी आरोप लगाया कि कलस्टर संगठन में कई ऐसे लोग हैं जो नियम विरुद्ध तरीके से तीन तीन पद पर कार्यरत रहकर अनुचित तरीके से शासकीय राशि प्राप्त कर रहे हैं। महिला समूहों की कई महिलाओं को समय पर राशि भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। बैंक सखी अर्चना मंडल ने मांग किया है कि कलस्टर के वर्ष 2021-2026 तक आय व्यय की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।

शिकायत की जांच कराई जाएगी

शिकायत की जानकारी मेरे पास मिला है। शिकायत की जांच कराई जाएगी और जो भी जांच रिपोर्ट आएगा, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

रेना जमील
कलेक्टर सुरजपुर

घटिया नाली निर्माण पर ठेकेदार पर गिरी गाज, 7 दिन में दोबारा निर्माण के आदेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर पंचायत बिश्रामपुर के वार्ड क्रमांक 13 स्थित माइनस कॉलोनी में आरसीसी नाली निर्माण में कथित अनियमितताओं और घटिया गुणवत्ता की शिकायत आखिरकार सही साबित होती दिखाई दे रही है। बिश्रामपुर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह डीके द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए शिकायत पत्र के बाद नगर पंचायत बिश्रामपुर ने मामले की जांच कर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 7 दिनों के भीतर क्षतिग्रस्त नाली का पुनर्निर्माण अपने स्वयं के खर्च पर कराने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि नगर पंचायत बिश्रामपुर के वार्ड क्रमांक 13 में कार्यादेश के तहत आरसीसी नाली का निर्माण कराया गया था।शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कार्यादेश में निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। नाली निर्माण में आवश्यक गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण निर्माण के कुछ समय बाद ही गत दिनों बारिश में लगभग 10 से 15 मीटर लंबी नाली धंसकर क्षतिग्रस्त हो गई।

कांग्रेस मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह डीके ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया था कि कार्य में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया तथा जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की उचित निगरानी नहीं की गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की भरपाई कराने की मांग की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत बिश्रामपुर के सीएमओ ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कार्यादेश के अनुरूप निर्मित आरसीसी नाली का एक हिस्सा गिर गया है, जो निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इसलिए ठेकेदार को सात दिवस के भीतर अपने स्वयं के व्यय पर कार्यादेश एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार नाली का पुनर्निर्माण करना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि इससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और सरकारी राशि के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने नगर पंचायत क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिवनंदनपुर की फौजी गली से हटाया गया खराब ट्रांसफार्मर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर पंचायत शिवनंदनपुर के वार्ड क्रमांक 3 स्थित फौजी गली में महीनों से खराब पड़े और नियम विरुद्ध लगाए गए विद्युत ट्रांसफार्मर को आखिरकार शनिवार को विद्युत विभाग ने हटा दिया है। गौरतलब है कि लगभग पखवाड़े भर पूर्व नपं शिवनंदनपुर के उपाध्यक्ष अंशुल गोयल ने कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग सूरजपुर को ज्ञापन सौंपकर वार्ड क्रमांक 3 के पानिकर भवन के सामने तथा वार्ड क्रमांक 2 निवासी नरेश मित्तल के घर से सटे स्थान पर स्थापित खराब विद्युत ट्रांसफार्मर को तत्काल हटाने की मांग की थी। ज्ञापन में उन्होंने बताया था कि ट्रांसफार्मर लंबे समय से बंद पड़ा है और उससे किसी भी उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके बावजूद विभाग द्वारा उसे नहीं हटाया जा रहा था। उपाध्यक्ष गोयल ने यह भी कहा था कि संकरी गली में लगे इस ट्रांसफार्मर के कारण आम लोगों और वाहन चालकों को आवागमन में

परेशानी होती है तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही ट्रांसफार्मर के आसपास कचरा जमा होने से क्षेत्र में गंदगी भी फैल रही थी। उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। ज्ञापन के बाद शनिवार को विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंच बंद पड़े ट्रांसफार्मर को हटाने की कार्रवाई पूरी की। ट्रांसफार्मर हटने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष अंशुल गोयल ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर कहा कि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिलना आवश्यक है।

ट्रेड यूनियनों की सदस्यता व्यवस्था हेतु नई गाइड लाइन जारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता व्यवस्था को पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रबंधन ने यूनियन सदस्यता शुल्क की कटौती के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब एक कर्मचारी की केवल एक ही यूनियन सदस्यता मान्य होगी, जबकि बहु-सदस्यता के मामलों का सत्यापन कर कर्मचारी से उसकी अंतिम पसंद ली जाएगी। सितंबर माह में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर में मिलने वाले सितंबर के वेतन से सदस्यता शुल्क की कटौती शुरू होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया मजदूरी संहिता 2019 की धारा 18 (2) (के) के तहत संचालित की जाएगी। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सदस्यता शुल्क कटौती के लिए केवल 31 मार्च तक जमा किए गए यूनियन सदस्यता प्राधिकरण फॉर्म को ही मान्य माना जाएगा। इसके आधार पर प्रत्येक क्षेत्र और यूनिट में कर्मचारियों की दो अलग-अलग सूचियां तैयार होंगी, एक एकल यूनियन सदस्यता वाले कर्मचारियों की तथा दूसरी बहु-यूनियन सदस्यता वाले कर्मचारियों की।

इन सूचियों को संबंधित यूनिट के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा 20 अगस्त तक उनकी प्रतियां संबंधित यूनियनों के अध्यक्ष एवं सचिव को उपलब्ध करा दी जाएंगी, ताकि किसी प्रकार की आपत्ति या त्रुटि होने पर समय रहते उसका निराकरण किया जा सके। ज्ञात हो कि नई व्यवस्था के तहत 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच सदस्यता सत्यापन का अभियान चलेगा। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक एचआर कार्यकारी और एक माइनिंग कार्यकारी की दो सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति बहु-सदस्यता वाले कर्मचारियों से उनकी अंतिम यूनियन पसंद प्राप्त करेगी और सदस्यता संबंधी विवादों का भी निपटारा करेगी।

प्रत्येक क्षेत्र में सत्यापन के लिए कम से कम दो दिन और अधिकतम तीन दिन निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी अवकाश या बीमारी के कारण निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनके लिए एक अतिरिक्त दिन रखा जाएगा। इन तिथियों का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय जेसीसी की बैठक में किया जाएगा। दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने नाम के सामने दर्ज यूनियन सदस्यता पर विवाद करता है या बहु-सदस्यता वाला कर्मचारी शपथपत्र देकर यह घोषित करता है कि वह किसी भी यूनियन का सदस्य नहीं है, तो उसके वेतन से सदस्यता शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी की एक से अधिक यूनियनों में सदस्यता दर्ज है और वह सत्यापन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी भी सदस्यता शुल्क कटौती नहीं होगी। हालांकि जिन कर्मचारियों की केवल एक ही यूनियन सदस्यता दर्ज है और वे सत्यापन के दौरान उपस्थित नहीं हो पाते, उनके मामले में सदस्यता शुल्क की कटौती यथावत की जाएगी।

क्षेत्रीय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि 25 सितंबर तक पूरी सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, ताकि सितंबर के वेतन से नई व्यवस्था के अनुसार यूनियन सदस्यता शुल्क की कटौती की जा सके।

एक शाम रफी के नाम में गूंजे मोहम्मद रफी के सदाबहार नगमे

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की स्मृति में कोयलांचल बिश्रामपुर के ऑडिटोरियम में गत दिनों एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के संगीत प्रेमियों और गायन के शौकीनों ने आपसी सहयोग से आयोजित इस संगीतमय संध्या में रफी साहब को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मोहम्मद रफी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद रफी साहब के लोकप्रिय गीत तुम मुझे यूं भुला न पाओगे की प्रस्तुति के साथ संगीतमय कार्यक्रम का आगाज हुआ। मंच पर एक-एक कर स्थानीय कलाकारों ने मोहम्मद रफी के सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मी सुदर्शन मंडल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें अपने जीवन में मोहम्मद रफी के कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला था। उन्होंने इसे अपने जीवन के सबसे यादगार क्षणों में से एक बताया। कार्यक्रम में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव, शिवनंदनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष रितेश जायसवाल, भाजपा नेता शितिकांत स्वाई, नगर पंचायत बिश्रामपुर उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, अनुपम फिलिप सहित अन्य उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में सुदर्शन मंडल, दीपक कुमार पॉल, उदय गिरी, रोमी मखीजा, केके सिंह, छोटू, चंद्रमा गिरी, पूजा देवांगन, फिरोज खान तथा कोक स्टूडियो के कलाकारों सहित क्षेत्र के अनेक संगीत प्रेमियों का विशेष योगदान रहा।

बस्तामुक्त विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी व महापुरुषों के जीवन चरित्र आधारित विविध कार्यक्रम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कलेक्टर रेना जमील के निर्देश पर प्रथम बस्तामुक्त शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुनियाडीह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र पर आधारित निबंध, चित्रकारी तथा भाषण प्रतियोगिता सह न्योता भोज का आयोजन किया गया। न्योता भोज पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्यनारायण जायसवाल एवं गीता जायसवाल के सौजन्य से पुत्र नितिन जायसवाल, पुत्रवधू आनंदी जायसवाल के प्रथम कन्या सुश्री शांभवी जायसवाल के अन्नप्रासन अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिपं सदस्य कलेश्वरी कुर्रे, पूर्व बीडीसी बाबूलाल राजवाड़े, मंडल अध्यक्ष राजेश राजवाड़े, सूरजपुर जिला के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद बाबू परमानंद के पौत्र अंकित कोसरिया, सांसद प्रतिनिधि राहुल जायसवाल, लखन लाल कुर्रे, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक रामसूरत जायसवाल, जनशिक्षक विजेंद्रलाल जायसवाल, एसएमसी अध्यक्ष कौशल्या राजवाड़े तथा आरती स्व सहायता समूह की फूलमेत राजवाड़े उपस्थित रहे। संस्था प्रमुख सीमांचल त्रिपाठी ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम शिवम विश्वकर्मा, द्वितीय वंदना राजवाड़े, तृतीय सानिया यादव, भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पायल राजवाड़े, द्वितीय शिवम विश्वकर्मा तथा तृतीय शांति सिंह, चित्रकारी प्रतियोगिता में प्रथम शांति सिंह, द्वितीय विनीता राजवाड़े तथा तृतीय दिबीका

विश्वकर्मा ने प्राप्त किया, जिन्हें कॉपी-पेन देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं सांत्वना पुरस्कार मिनाक्षी सिंह, हेमलता, विवेक विश्वकर्मा, नगीना यादव, ऋतु राजवाड़े, कविता सिंह, रिया देवांगन, संगीता यादव, वंदना राजवाड़े, प्रतिमा विश्वकर्मा, मनीता राजवाड़े, रविंद्र सिंह, पायल, पूरब सारथी, कविता आराध्या राजवाड़े, रिया विश्वकर्मा, अमन राजवाड़े, धनेश्वर सारथी, जान्हवी तथा रचना देवांगन को दिया गया। मुख्य वक्ता जिले के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद बाबू परमानंद के पौत्र अंकित कोसरिया द्वारा बाबू परमानंद के जीवन वृतांत पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि वे हरिद्वार स्थित आर्य समाज से बचपन से जुड़े हुए थे। आर्य समाज के नेतृत्व में देश को आजादी दिलाने खातिर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय हुए और अंग्रेजों के प्रताड़ना से हैदराबाद के जेल में ही आप अल्पायु में ही शहीद हो गए।संस्था द्वारा अंकित कोसरिया का अंगवस्त्र-श्रीफल से सम्मानित किया गया। संस्था प्रमुख की मांग पर सत्यनारायण जायसवाल द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने खातिर दस नग कबड्डी शूज संस्था के खेल मंत्री कैलास राजवाड़े के नेतृत्व में बालिका कबड्डी टीम को प्रदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षक रिजवान अंसारी, बाल कैबिनेट के मंत्री दीपक राजवाड़े, वर्षा राजवाड़े अध्यक्ष युथ एवं इको क्लब, खुशी, रिया, निशा राजवाड़े, संध्या, घरभरन राजवाड़े तथा कुश देवांगन सक्रिय रहे।

अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता अभियान, श्रमदान से दिया स्वच्छता का संदेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशानुसार तथा सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग श्री घनश्याम कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ निधि से संचालित अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट, सूरजपुर में गुरुवार को विशेष स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना तथा स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक श्री सोमनाथ साहू एवं शिक्षक श्री रोहित तिवारी के नेतृत्व में हुई। लगभग 150 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अभियान में भाग लिया। विद्यार्थियों ने हाथों में झाड़ू, तगारियां और कचरा पात्र लेकर संस्थान परिसर, आसपास की गलियों तथा मुख्य मार्ग की व्यापक सफाई की। उन्होंने सड़क किनारे फैले प्लास्टिक कचरे, पॉलिथीन, सूखे पत्तों एवं अन्य अपशिष्ट को एकत्रित कर उनके उचित निस्तारण की व्यवस्था की। पूरे अभियान के दौरान विद्यार्थियों में सेवा भावना, अनुशासन और उत्साह का विशेष वातावरण देखने को मिला।

अभियान में जिले के श्रम पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ठाकुर, नगरपालिका परिषद सूरजपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मनीष कुमार, संस्थान के शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। श्रम पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि 'स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का आधार है। जब युवा स्वयं आगे बढ़कर श्रमदान करते हैं, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। शिक्षा के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन ही वास्तविक ज्ञान की पहचान है।' उन्होंने विद्यार्थियों से सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करने तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

के.आर. टेक्निकल कॉलेज में 'एआई इंटीग्रेशन इन क्लासरूम टीचिंग' विषय पर आयोजित पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफल समापन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

के.आर. टेक्निकल कॉलेज, संजय नगर में ₹एआई इंटीग्रेशन इन क्लासरूम टीचिंग₹ विषय पर आयोजित पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का शुक्रवार को गरिमामय समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर के माननीय कुलपति डॉ. राजेन्द्र लकपाले रहे। उन्होंने महाविद्यालय द्वारा विकसित एलएमएस पोर्टल एवं एआई पोर्टल का शुभारंभ किया तथा कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले प्रतिभागियों एवं रिसोर्स पर्सन को प्रमाण-पत्र प्रदान किए।अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन में डॉ. राजेन्द्र लकपाले ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा जगत में नवाचार, गुणवत्ता एवं अनुसंधान की नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है।शिक्षकों को समय के साथ स्वयं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना होगा ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं भविष्य उन्मुख शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने महाविद्यालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा प्रदान करेंगे।यह पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 27 से 31 जुलाई 2026 तक के.आर. टेक्निकल कॉलेज के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) एवं कंप्यूटर विज्ञान विभाग द्वारा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर के कंप्यूटर विज्ञान विभाग तथा छत्तीसगढ़ सोसायटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित किया गया।समारोह का शुभारंभ महाविद्यालय की डायरेक्टर डॉ. रीनू जैन के स्वागत उद्बोधन से हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों, रिसोर्स पर्सन एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्तरदायित्वपूर्ण एवं प्रभावी उपयोग समय की आवश्यकता है तथा इसी उद्देश्य से महाविद्यालय निरंतर नवाचारपूर्ण पहल कर रहा है।इसके पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य एवं कंप्यूटर विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. रितेश वर्मा ने एलएमएस पोर्टल एवं एआई पोर्टल का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि इन पोर्टलों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन शिक्षण, मूल्यांकन, डिजिटल शिक्षण संसाधन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विभिन्न सुविधाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी।कार्यक्रम की अध्यक्षता

महाविद्यालय के उपाध्यक्ष श्री राहुल जैन ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि के.आर. टेक्निकल कॉलेज गुणवत्तापूर्ण, नवाचारपूर्ण एवं तकनीक-सक्षम शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा भविष्य में भी ऐसे शैक्षणिक एवं कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अतिथियों, माननीय कुलपति, रिसोर्स पर्सन, प्रतिभागियों एवं आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त किया कार्यक्रम का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभागाध्यक्ष डॉ. एच. एस. होता तथा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर के कंप्यूटर विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. रेशम लाल प्रधान की गरिमामयी उपस्थिति के साथ हुआ था। उद्घाटन अवसर पर महाविद्यालय की वर्चुअल लैब का भी शुभारंभ किया गया।पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत, एआई आधारित पाठ योजना निर्माण, अध्ययन सामग्री तैयार करना, प्रश्न-पत्र निर्माण, मूल्यांकन प्रणाली, विभिन्न एआई टूल्स का प्रभावी उपयोग, व्यक्तिगत अधिगम, स्वचालित प्रतिपुष्टि प्रणाली, गूगल एआई स्टूडियो, नेटलिफाई प्लेटफॉर्म, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, विषयानुसार एआई अनुप्रयोग, संस्थागत एआई नीति, एआई नैतिकता, शैक्षणिक ईमानदारी, पक्षपात एवं डेटा गोपनीयता जैसे समसामयिक विषयों पर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में डॉ. रीनू जैन, डॉ. रेशम लाल प्रधान, डॉ. एच. एस. होता, डॉ. एच. एस. पी. टोंडे, डॉ. मोहन राव मामडीकर, डॉ. हिमांशु साहू, श्री फैजुल हुडा, डॉ. जया शर्मा एवं डॉ. रितेश वर्मा ने रिसोर्स पर्सन के रूप में विशेषज्ञ व्याख्यान एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए। प्रथम दिवस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूल अवधारणाओं, शिक्षण में एआई के उपयोग तथा एआई आधारित प्रश्न-पत्र निर्माण पर प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय दिवस में एआई आधारित पाठ योजना निर्माण एवं अध्ययन सामग्री तैयार करने की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तृतीय दिवस में विभिन्न एआई टूल्स, स्वचालित प्रतिपुष्टि प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। चौथे दिवस प्रतिभागियों ने गूगल एआई स्टूडियो, नेटलिफाई प्लेटफॉर्म एवं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अपने मोबाइल एवं लैपटॉप पर अभ्यास करते हुए डिजिटल शिक्षण सामग्री एवं वेबसाइट तैयार की। अंतिम दिवस में संस्थागत एआई नीति, एआई नैतिकता, शैक्षणिक ईमानदारी, पक्षपात तथा डेटा गोपनीयता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान एवं विचार-विमर्श आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी श्री विनितेश गुप्ता ने किया।समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी प्रशिक्षण बताया। कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों ने एआई आधारित शिक्षण, डिजिटल शिक्षण सामग्री निर्माण, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आधुनिक एआई टूल्स के प्रभावी उपयोग, संस्थागत एआई नीति, एआई नैतिकता तथा डेटा गोपनीयता जैसे विषयों पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम उच्च शिक्षा में नवाचार, गुणवत्ता एवं तकनीक-सक्षम शिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में के.आर. टेक्निकल कॉलेज की एक महत्वपूर्ण एवं सफल पहल सिद्ध हुआ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा रक्तदान शिविर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामानुजनगर में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता शिवम्दुबे ने महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ रक्तदान कर मानव सेवा का प्रेरणादायी संदेश दिया।इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि ₹रक्तदान महादान है।एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद के लिए जीवनदान साबित हो सकता है।रक्तदान कर शिविर को सफल बनाने के लिए बी एम ओ डां प्रियंका शर्मा ने शिवम को पुष्पगुच्छ भेंट किया।

जशपुर में अमानक पनीर एवं डेयरी एनालॉग उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

भ्रामक दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर लगाई गई रोक

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर - भोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने बड़ा निर्णय लिया है।लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (एनालॉग पनीर) तथा ऐसे गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जशपुर द्वारा भी जिले के सभी संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों एवं आम नागरिकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 एवं 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है। विभागीय परीक्षण, प्रयोगशाला विश्लेषण एवं जोखिम मूल्यांकन के आधार पर यह पाया गया कि कुछ उत्पाद वास्तविक दूध से निर्मित नहीं होने के बावजूद पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों के रूप में उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे थे, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। आदेश के अनुसार ऐसे सभी उत्पाद प्रतिबंधित रहेंगे, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया हो अथवा जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग अथवा प्रदर्शन उपभोक्ताओं को वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का भ्रम उत्पन्न करता हो। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज एवं मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे विधिवत मानकीकृत उत्पाद इस प्रतिबंध के दायरे में शामिल नहीं हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अंतिम नियम जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जशपुर ने जिले के सभी खाद्य कारोबार संचालकों, डेयरी उत्पाद निमार्ताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से शासन के निदेर्शों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।साथ ही आम उपभोक्ताओं से भी केवल प्रमाणित एवं मानक गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादों का ही उपयोग करने तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी विभाग को देने का आग्रह किया गया है।विभाग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रामानुजनगर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन, समाजसेवियों व स्काउट-गाइड ने बढ़-चढ़कर किया रक्तदान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर में शनिवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों, सामाजिक कार्यकताओं, स्काउट-गाइड सदस्यों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया।इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं ने मानव सेवा का संदेश देते हुए अधिक से अधिक लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका शर्मा ने सभी रक्तदाताओं का स्वागत करते हुए उनके इस मानवीय कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि एक यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचा सकता है।उन्होंने सभी नागरिकों से समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करने का आह्वान किया।शिविर में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य, स्काउट एवं गाइड के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। रक्तदान करने वालों में डॉ. प्रियंका शर्मा, डॉ. सीमा त्रिपाठी, राजेश द्विवेदी, ऋषि दूबे, अभिषेक उपाध्याय, शिक्षक योगेश साहू, संदीप तिवारी, श्रीकांत पांडेय, रघुनाथ जायसवाल, शिवम दूबे सहित अनेक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। रक्तदान के पश्चात सभी रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसे शिविर समाज में मानवता, सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए समय पर रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर के सफल आयोजन में स्वास्थ्य विभाग की टीम, स्काउट-गाइड संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवकों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने नियमित रक्तदान करने तथा अन्य लोगों को भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।

हायर सेकेंडरी स्कूल सरहरी में एकबैगलेस डे पर जमेगा देशभक्ति का रंग

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सरहरी/प्रतापपुर। किताबों के बोझ से मुक्त होकर बच्चे अब देशभक्ति, कला और संस्कृति सीखेंगे। कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक (समग्र शिक्षा), सूरजपुर के निर्देश पर 1 अगस्त, शनिवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरहरी में बैगलेस डे को विशेष और प्रेरणादायी बनाने की तैयारी है। प्राचार्य दिलीप तिवारी के मार्गदर्शन में इस दिन को यादगार बनाने के लिए भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है।

आयोजन का सबसे खास हिस्सा होगा प्रेरणा सत्र। विद्यालय प्रबंधन ने सूरजपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र कमलेश कोसरिया को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। विद्यालय परिवार द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। वे विद्यार्थियों को देश की आजादी में सेनानियों के त्याग, संघर्ष और अनसुने प्रसंगों से रूबरू कराएंगे। जिला कार्यालय के आदेश पर छात्रों द्वारा महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र व पेंटिंग तैयार किए जा रहे हैं।एक अगस्त को इनकी भव्य प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही देशभक्ति रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया जाएगा।कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों को सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। पर्यावरण संरक्षण और भाईचारे का संदेश देने के लिए स्कूल परिसर में राष्ट्रीय एकता सांप्रदायिक सद्भावना पौधारोपण के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जाएगा। इसमें अतिथि, शिक्षक और बच्चे मिलकर पौधे लगाएंगे।

कार्यक्रम के संयोजक और सरगुजा संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध कर चुके राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता अजय कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जगाना है। सेनानी के परिजनों से सीधा संवाद बच्चों को सही मार्ग पर चलने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा।विद्यालय की इस पहल को लेकर छात्र-छात्राओं में जबरदस्त उत्साह है। शिक्षकों का मानना है कि बैगलेस डे का यह आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

व्याकरण ही नहीं, सत्यता और संतुलन ही भाषा की वास्तविक शुचिता-मनोज दयाल

रायपुर।छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के युगद्रष्टा मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई के अवसर पर एक ऐतिहासिक पहल की गई। इस पावन अवसर पर विश्वविद्यालय में 'बौद्धिक विमर्श इकाई' की स्थापना की गई, जिसके तहत ₹सार्वजनिक जीवन में भाषा की शुचिता₹ विषय पर एक विशेष राष्ट्रीय विमर्श आयोजित हुआ। इस अवसर पर कुलपति प्रो. डॉ. मनोज दयाल ने मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक एवं पत्रकारिता योगदान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने अपनी धारदार लेखनी से समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार किया और आम आदमी की सहज-सरल बोली को साहित्य के उच्च शिखर पर स्थापित किया। आज के दौर में भाषा की शुचिता का दायरा केवल व्याकरणिक शुद्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सत्यता, वैचारिक संतुलन और वस्तुनिष्ठता का समाहित होना अनिवार्य है।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में संवाद का सकारात्मक प्रयोग समाज को जोड़ता है, जबकि मयार्दाहीन और कलुषित भाषा सामाजिक विभाजन को जन्म देती है।कुलसचिव श्री सुनील शर्मा ने कहा कि सफल संवाद वही है जो श्रोता की समझ और गरिमा को ध्यान में रखकर किया जाए।सार्वजनिक जीवन में हमारी भाषा का स्तर ही हमारे व्यक्तित्व और विचारों का दर्पण होता है।

संस्कारों का हस्तांतरण अगली पीढ़ी को ठीक तरीके से न हो तो उस समाज का क्षय होना निश्चित है

अश्लीलता दबे पांव नहीं, सीना तानकर इंस्टा यूट्यूब के दरवाजे आपके घर तक आई है- संतोष दास सरल

आलेख

इन दिनों नीट पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के हिंसक और अश्लील विरोध प्रदर्शन को लेकर पूरे सोशल मीडिया में प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं के अश्लील गाली-गलौज वाले वीडियो तैर रहे हैं। कुछ लोगेंल्ल- के इस शर्मनाक कृत्य को नया ट्रेंड बताकर महिमामंडित कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे नए भारत के युवाओं की ताकत बता रहे हैं। भारतीय समाज के बीच से निकलकर आए ये किशोर युवा आखिर कौन हैं जिन्हें मान, मयार्दा, परंपरा, संस्कारों का भान नहीं? याद रखिए! ये अश्लीलता दबे पांव नहीं, सीना तानकर इंस्टा यूट्यूब के दरवाजे आपके घर तक आई है, और विडंबना देखिए आप इसेंल्ल- की नई सोंच कहकर इसका स्वागत व अभिनंदन कर रहे हैं। आप किसी सरकार, किसी राजनीतिक दल या फिर किसी विचारधारा के विरोधी तो हो सकते हैं परंतु जिस समाज में आप पले-बढ़े और जिस समाज से संस्कार लेकर आपने जीने का तौर-तरीका सीखा आप उसके विरोधी नहीं हो सकते।

जन्तर-मन्तर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर पूरे देश ने जो अश्लीलता, नग्नता और भौंडापन देखा उसने देश के पंद्रह-सत्रह साल केंल्ल- का एक भयावह, विकृत स्वरूप प्रस्तुत कर पूरे भारतीय समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय समाज पढ़े लिखे युवाओं की असभ्यता पर हतप्रभ और किंकर्तव्यविमूढ़ है। अपने परदादा की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ऐसी गंदी गालियां जिसे कानों से सुन पाना सम्भव ना हो उसे युवा किशोर लड़कियों के मुख से सुननी पड़ जाए तो समाज को चिंता नहीं, चीत्कार करने की आवश्यकता है। ेल्ल- के ऐसे अमर्यादित असामान्य व्यवहार पर यदि आप इसलिए खुश हैं कि आप किसी व्यक्ति या सरकार के विरोधी हैं और विरोध में तो सब जायज है वाली बात पर यकीन करते हैं तो याद रखिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, सीने पर खंजर चला रहे हैं। समाज की बुराइयों को देखकर खुश होने वाले व्यक्ति के परिवार की संतानें कभी न कभी दुनिया के सामने अपने परिवार को शर्मिन्दा कर कहीं का नहीं छोड़ती। किसी भी समाज में व्याप्त संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बहुत सहेजकर व संभालकर सौंपे जाते हैं और यदि संस्कारों का हस्तांतरण अगली पीढ़ी को ठीक तरीके से न हो तो उस समाज का क्षय होना निश्चित है।

जंतर-मंतर के अश्लील प्रदर्शन को युवाओं में उपजा भारी आक्रोश बताने वाले ये भूल जाते हैं कि इससे भी कई गुना ज्यादा आक्रोश निर्भया कांड को लेकर वर्ष 2012 में था जिसने देश के हर गली मुहल्ले को आंदोलित किया था। देश में भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हजारे के विरोध प्रदर्शन से बड़ा ऐसा कोई अनशन या आंदोलन नहीं हुआ जिसका समर्थन देश के प्रत्येक युवा व नागरिकों ने किया हो, परंतु मजाल है कि प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसी भी युवा की तख्ती पर तत्कालीन सरकार या व्यवस्था के लिए किसी ने गालियां लिखी हुई देखी हो? या किसी प्रदर्शनकारी युवा की जुबान से पुलिस प्रशासन व सरकार के विरुद्ध गंदी अश्लील गालियों की बौछार किसी ने देखी सुनी हो? रामलीला मैदान और जंतर-मंतर दोनों आंदोलनों की कोई तुलना नहीं क्यूंकि अन्ना आंदोलन अपने आदर्श, मयार्दा व अनुशासन के लिए याद किया जाता है तो जंतर-मंतर का नीट पेपर लीक आंदोलन अपनी फूहड़ता और अश्लीलता के लिए।

जंतर-मंतर का आंदोलन खत्म होने के बाद से देश केंल्ल- की सोंच और दिशा क्या है? यह चिंतन पूरे देश और समाज को भयाक्रांत कर रही है। कहते हैं हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से बेहतर होती है, क्या वर्तमान पीढ़ी के संदर्भ में भी यह बात कही जा सकती है? क्या सदियों से चले आ रहे मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में संस्कारों के बिना केवल आधुनिक तकनीक और अक ज्ञान के सहारे वर्तमान पीढ़ी अपनी पहचान बनाने की दिशा में अब बहुत आगे निकल चुकी है? क्या आधुनिक तकनीक के प्रभाव में वर्तमान पीढ़ी स्वच्छंद होकर लोक-लाज के भय से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है?

इन सवालों के जवाब यदि आज नहीं ढूँढे गए तो यकीन मानिए आने वाले समय में भारतीय समाज की पहचान उनके संस्कार व आदर्श अपना अस्तित्व बचाने संघर्ष करते दिखेंगे..!!

सादर..
आलेख-
संतोष दास 'सरल'
समसामयिक विश्लेषक

सम्पादकीय

विद्वानों पर टिप्पणी करने से बचें राजनेता

विद्वान और शिक्षाविद देश की अमूल्य धरोहर होते हैं। वे किसी भी दल, धर्म, जाति या दल से ऊपर होते हैं। ऐसे में राजनेताओं को विद्वानों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के नवगठित शिक्षा सुधार समिति के एक सदस्य आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि को गोमूत्र विशेषज्ञ कहे जाने पर लोकसभा में हंगामा हो गया। प्रोफेसर कामकोटि गोमूत्र के कथित औषधीय गुणों पर अपनी राय के कारण पहले भी चर्चा में रहे हैं। इस मामले को लेकर 215 वर्तमान और पूर्व कुलपतियों तथा शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखकर इसी चिंता को सामने रखा है। पत्र में कहा गया है कि किसी शिक्षाविद् से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके विचारों और शोध पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर उनका मजाक उड़ाना उचित नहीं है। प्रो. कामकोटि को पारंपरिक ज्ञान या किसी वैज्ञानिक परिकल्पना पर अपनी राय रखने का अधिकार है। यदि उनके किसी दावे या विचार से असहमति है तो उसके प्रमाणों और वैज्ञानिक आधार को चुनौती दी जानी चाहिए। वैज्ञानिक विमर्श की यही स्वस्थ परंपरा है। प्रो. वी. कामकोटि कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद् हैं तथा आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। उन्होंने इसी संस्थान से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा और पीएचडी हासिल की। उनके नेतृत्व में उस टीम ने भारत के स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति' के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों में भी भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति की किसी एक राय को आधार बनाकर उसकी पूरी विद्वत्ता को एक उपहासपूर्ण संबोधन में सीमित कर देना निश्चित रूप से स्वस्थ बहस का तरीका नहीं हो सकता। यदि गोमूत्र के औषधीय गुणों को लेकर कोई दावा वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो वैज्ञानिक समुदाय और राजनेताओं को उसके प्रमाण मांगने चाहिए। शोध को शोध से चुनौती दी जानी चाहिए, व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा और परीक्षा सुधार जैसे गंभीर विषयों पर बनी समितियों में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। पेपर लीक जैसी समस्या केवल शिक्षा विभाग की समस्या नहीं है। इसमें तकनीक, साइबर सुरक्षा, प्रशासन, खुफिया तंत्र और परीक्षा संचालन से जुड़े विशेषज्ञों की भी भूमिका हो सकती है। राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार और जिम्मेदारी है, लेकिन व्यक्तिगत कटाक्ष और उपहास से बहस का स्तर गिरता है। सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी यही कसौटी लागू होनी चाहिए। किसी वैज्ञानिक, शिक्षक, न्यायविद् या अन्य विद्वान की राजनीतिक विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान बना रहना चाहिए। शिक्षाविदों की आपत्ति को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनका संदेश स्पष्ट है कि विचारों पर कठोर बहस कीजिए, प्रमाण मांगिए, गलत दावों को तथ्यों से खारिज कीजिए, लेकिन विद्वानों का उपहास मत उड़ाइए। भारत को आज ऐसी ही संवाद संस्कृति की जरूरत है, जिसमें राजनीतिक असहमति के बावजूद ज्ञान और विद्वता के प्रति सम्मान बना रहे।

मुद्दा
रोहित कौशिक

देश में उच्च शिक्षा के लिए नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को चेताया है कि वे प्रवेश लेने से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता, संबंधित कोर्स और डिग्री की मंजूरी के बारे में सही तरीके से जांच कर लें। यूजीसी ने सभी राज्यों व विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी और निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की डिग्री मान्य नहीं होगी। दरअसल, हर साल देश के अनेक युवा फर्जी शिक्षण संस्थानों के चक्कर में फंस जाते हैं। बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इन दिनों देश में कई संदिग्ध शिक्षण संस्थान अनेक तरह की फर्जी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं।

फर्जी शिक्षण संस्थानों पर नकेल जरूरी

देश में उच्च शिक्षा के लिए नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को चेताया है कि वे प्रवेश लेने से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता, संबंधित कोर्स और डिग्री की मंजूरी के बारे में सही तरीके से जांच कर लें। यूजीसी ने सभी राज्यों व विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी और निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की डिग्री मान्य नहीं होगी। दरअसल, हर साल देश के अनेक युवा फर्जी शिक्षण संस्थानों के चक्कर में फंस जाते हैं। बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इन दिनों देश में कई संदिग्ध शिक्षण संस्थान अनेक तरह की फर्जी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आते भी रहते हैं। ऐसे संस्थानों के संदिग्ध क्रियाकलापों का खुलासा होने पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ऐसे संस्थान फिर शुरू हो जाते हैं।

पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती में फर्जी बीपीएड डिग्रियां बांटने वाले उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय पर कार्रवाई भी की गई थी। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने एक निजी विश्वविद्यालय में चल रहे फर्जी डिग्री घोटाले का भंडाफोड़ कर बड़ी कार्रवाई की थी। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी डिग्रियां, प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट समेत अन्य कई तरह की सामग्री बरामद की थीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि एक तरफ फर्जी डिग्रियों के माध्यम से शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को ठग रहे हैं। कुछ समय पहले यूजीसी ने देश भर में खुले कई फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की थी। इन विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह की डिग्री देने का अधिकार नहीं है। शर्मनाक यह है कि ये विश्वविद्यालय हाल ही में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि कई वर्षों से चल रहे हैं। सही जानकारी के अभाव में हजारों छात्र इन फर्जी विश्वविद्यालयों के भंवर में फंस जाते हैं। सवाल यह है कि कई वर्षों से चल रहे इन फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर इन पर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो हजारों छात्रों के भविष्य पर मंडराते खतरे को दूर किया जा सकता था। दरअसल, ऐसे मामलों में हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। यूजीसी समय-समय पर विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराता रहता है। सवाल यह है कि जब यूजीसी और सरकार को फर्जी विश्वविद्यालयों की जानकारी है तो उनके संचालकों की धरपकड़ कर इन अवैध विश्वविद्यालयों को बन्द क्यों नहीं कराया जाता? फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित कर देने मात्र से ही यूजीसी और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाते। यह विडम्बना ही है कि आज गली-गली में निजी शिक्षा संस्थानों की बाढ़ आ गई है। इनमें से कुछ शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलाप संदिग्ध हैं। सवाल यह है कि शिक्षा को व्यापार बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है ? नब्बे के दशक में शुरू हुई उदारीकरण की आंधी ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि इससे पहले भी कुछ राज्यों में उच्च शिक्षा निजी हाथों में जा चुकी थी, लेकिन नब्बे के दशक में

व्यापक रूप से पूरे देश में शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने का काम किया गया। सरकार ने खुद खाओ, खुद कमाओ की नीति के तहत शिक्षा का निजीकरण करते हुए गर्व का अनुभव किया। सरकार की इस नीति से अनेक औद्योगिक घराने अपना पारम्परिक व्यापार त्याग कर शिक्षा के क्षेत्र में कूद पड़े। उनके लिए यह उपक्रम सिर्फ एक व्यापार को त्याग कर दूसरे व्यापार को अपनाना भर था। इनकी देखा देखी छोटे व्यापारी भी इस क्षेत्र की तरफ भागने लगे। हमारे देश में प्रारम्भ से ही शिक्षा प्रदान करने का प्रायोजन धर्मार्थ माना गया है। इसलिए सरकार की नई नीति के तहत शिक्षा प्रदान करते हुए इन सभी व्यापारियों को धर्म एवं समाज सेवा का आवरण अपने आप मिल गया। धर्म एवं समाजसेवा के आवरण में मुनाफा कमाने का इससे अच्छा साधन और कोई नहीं हो सकता था। इसलिए शिक्षा के निजीकरण ने एक नए किस्म के व्यापार को जन्म दिया, जिसमें मुनाफा तो पूरा था, लेकिन व्यापारी की छवि मुनाफा कमाने वाले की नहीं बल्कि उपकार करने वाले की थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि एक के बाद एक सरकारें इसी नीति पर चलती रहीं। सभी सरकारों द्वारा धड़ल्ले से निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाती रही। सरकारें बार-बार ये बताती रहीं कि हमारे देश के हालात को देखते हुए अभी और विश्वविद्यालय खोले जाने की जरूरत है। इस हड़बड़ी में शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। कई बार जानबूझकर इन विसंगतियों को नजरअन्दाज किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षा जगत से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध रहती है। अपना मुंह बन्द रखने और अवैध रूप से मान्यता देने के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा इन अधिकारियों को मोटी रकम दी जाती है। स्पष्ट है कि शिक्षा जगत में फैले भ्रष्टाचार को बढ़ाने में इस क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और विभिन्न समितियों में स्थान प्राप्त प्रोफेसर्स भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल, निजी शिक्षण संस्थानों के मालिक विभिन्न राजनेता और अन्य प्रभावशाली लोग होते हैं इसलिए इस मामले में जानबूझकर चुप्पी साध ली जाती है। ऐसे मामलों में जितने दोषी विश्वविद्यालयों के संचालक हैं, उतनी ही दोषी सरकार और उससे जुड़े अधिकारी भी हैं।

आजादी के बाद कुछ हद तक शिक्षा नीति की कमजोरी को दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए। एक बार फिर शिक्षा नीति में परिवर्तन की कोशिशें हो रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे नीति-निर्माता शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की हड़बड़ाहट में अपना विवेक खोकर कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को ठेस पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति में परिवर्तन करना है या फिर इस परिवर्तन के माध्यम से शिक्षा की कमजोरियों को दूर करना है? हमारे नीति-निर्माताओं की नीतियों एवं क्रियाकलापों को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा नीति में परिवर्तन करना भर है। इस दौर में उच्च शिक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कहने को तो शिक्षा नीति में काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अभी भी लीक ही पीट रहे हैं। शिक्षा जगत में मौजूद इन विसंगतियों के बीच नई शिक्षा नीति में भी एक बार फिर निजी शिक्षण संस्थानों को अनेक तौर-तरीकों से पनपने का मौका दिया गया है। सवाल यह है कि क्या ये संस्थान शिक्षा के मूल उद्देश्य को पूरा करने की तरफ ध्यान देंगे? अब समय आ गया है कि सरकार निजीकरण की आड़ में पनपे संदिग्ध विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों पर गम्भीरता से ध्यान दें ताकि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाया जा सके।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जयंती विशेष
बाल मुकुन्द ओझा

आम आदमी की बोली के रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद

आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। ग्रामीण जन जीवन के चितेरे लेखक मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आज भी न केवल प्रासंगिक हैं अपितु हिंदी साहित्य की अमर अजय रचनाएं हैं। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास विधा में एक नई और जीवंत परंपरा की शुरुआत की। उनकी प्रत्येक रचना सच्चाई के इर्दगिर्द घूमती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आम आदमी की समस्याओं और पीड़ाओं को यथार्थ रूप से चित्रित किया। यही कारण है कि वे साहित्य के अमर अजर रचनाकार के रूप में ख्यात हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपतराय था। प्रेमचंद ने 1901 में उपन्यास लिखना शुरू किया। कहानी 1907 से लिखने लगे। उर्दू में नवाबराय नाम से लिखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों लिखी गई उनकी कहानी सोजेवतन 1910 में जब्त की गई। उसके बाद अंग्रेजों के उत्पीड़न के कारण वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। 1923 में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1930 में हंस का प्रकाशन शुरु किया। इन्होंने मर्यादा, हंस, जागरण तथा माधुरी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। ये आधुनिक कथा साहित्य के जन्मदाता कहलाए। उन्हें कथा सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। इन कहानियों में आम आदमी की घुटन, चुभन व कसक को अपनी कहानियों में उन्होंने प्रतिबिम्बित किया। उनकी कहानियों में रूढ़ियों, अंधविश्वासों, अंधपरंपराओं पर कड़ा प्रहार किया गया है वहीं दूसरी ओर मानवीय संवेदनाओं को भी उभारा गया है। ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, दो बैलों की आत्म कथा जैसी कहानियां कालजयी हैं। तभी तो उन्हें कलम का सिपाही, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्रेमचंद के साहित्य में समस्याओं को न केवल उठाया गया है, बल्कि उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या, गबन में नारी के आभूषण प्रेम की समस्या, कर्म भूमि में जमीदारों के अत्याचारों का पूंजीपतियों की हठधर्मिता की समस्या, निर्मला में अनमेल विवाह की समस्या आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार प्रेमचंद अपने साहित्य में इन समस्याओं को उनके दुष्प्रभावों से परिचित कराते हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। प्रेमचंद का साहित्य ग्रामीण जीवन की संपूर्ण झांकी को प्रस्तुत करता है। गोदान उपन्यास तो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहलाता है। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा आदि कहानियां भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिखी गई हैं। इन रचनाओं में उन्होंने ग्रामीणों के प्रति एक नवीन व स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाकर उनकी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से उठाया है। मुंशी प्रेमचंद एक महान कथाकार के साथ-साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी रहे हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम सामाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया है। मुंशी प्रेमचंद देश के ऐसे पहले रचनाकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलस्मी और ऐयारी से बाहर निकाल कर जमीनी हकीकत से परिचय कराया। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम लोगों विशेषकर मेहनतकश वर्ग की भावनाओं और सच्चाइयों को वर्णित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की वास्तविक और जमीनी समस्याओं से देशवासियों को अवगत कराया। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। वह आम भारतीय के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में ऐसे नायक हुए,जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। उन्होंने सरल,सहज और जनसाधारण की बोल-चाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से समाज के सामने प्रस्तुत किया। प्रेमचंद हिन्दी साहित्य के युग प्रवर्तक माने गए। उनकी रचनाओं में समाज का पूरा 'परिवेश' उसकी 'कुरूपता' और 'असमानता', 'छुआछूत', 'शोषण' की विभीषिका कमजोर वर्ग और स्त्रियों का दमन आदि वास्तविकता प्रकट हुई है। उन्होंने सामान्य आदमी का जीवन अत्यंत निकट से देखा था तथा खुद उस जिंदगी को भोगा भी था। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिन्दी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया, जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों जमकर विरोध किया और आम आदमी की कहानी उनकी बोलचाल की भाषा में चित्रित की।

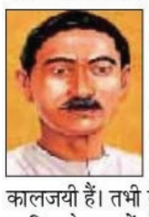

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

कथनी और करनी में न हो कोई अंतर

संकलित
दर्शन

सभी के हित का ध्यान रखते हुए मनसा, वाचा, कर्मणा अपने दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वाह करना कर्त्तव्य है। कर्त्तव्य का पालन यदि समुचित रूप से किया जाता है तो जीवन पूर्णतः गौरवान्वित बनता है। जो कर्त्तव्यनिष्ठ है। वह अपने करणीय कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। वह परमार्थ पोषक एवं प्रामाणिक होता है। वह

जैसा रहता है, वैसा ही करता भी है। ऐसी कथनी-करनी की एकरूपता से वह समाज में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है और प्रत्येक उससे प्रेरणाएं ग्रहण करता है। कर्त्तव्य परिपालन की बात करना और कर्त्तव्य परिपालन के नाम पर शोर-शराबा मचाना अलग बात है और कर्त्तव्यों के क्षेत्र में बिना किसी शोर-शराबे के समर्पित हो जाना अलग बात है। आज हम देखते हैं कि कर्त्तव्यों के परिपालन के लिए अक्सर लम्बे-चौड़े उपदेश दिये जाते हैं, पर जब कर्तव्य निर्वाह का अवसर आता है तो व्यक्ति दायें-बायें देखने लगता है। कटु सत्य तो यह है कि आज कर्त्तव्यों की चर्चा करने वाले लाखों हैं, पर कर्त्तव्यों के पावन पथ पर गतिशील होने वाले विरले ही हैं। कई बार मुझे चिंतन के क्षणों में लगता है कि आज व्यक्ति कर्त्तव्यों से विमुख हो गया है। इस विमुखता के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अराजकता और अशांति का विस्तार हुआ है। कर्त्तव्यों के पावन क्षेत्र से भटककर कोई व्यक्ति कभी भी शांति का अहसास नहीं कर सकता। जीवन का गौरव और उसकी सार्थकता कर्त्तव्य पालन में ही है।

संतान गुस्सा हो तो उसे शांत करने की कोशिश करें

संकलित
प्रेरणा

पुराने समय में एक दिन शिव जी और पार्वती जी ने विचार किया कि अब गणेश और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहिए। ये विचार करने के बाद उन्होंने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया और दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी

तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे हुए थे। गणेश जी ने तुरंत ही माता-पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया कि आप दोनों ही मेरे लिए संसार हैं। दूसरी ओर, कार्तिकेय स्वामी को संसार की परिक्रमा करके लौटने में थोड़ा समय लग गया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। गणेश जी को विवाहित देखकर कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। उन्होंने शिव-पार्वती से कहा कि आपने ये सही नहीं किया है। क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिव जी और देवी पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को समझाने की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन कार्तिकेय शांत नहीं हुए। शिव-पार्वती समझ गए कि कार्तिकेय बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये वापस भी नहीं आएगा। तब दोनों ने तय कि वे ही कार्तिकेय से मिलने जाते रहेंगे। इसके बाद हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्रीपर्वत पर आती हैं। ऐसी मान्यता है। श्रीपर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है।

वक्फ प्रशासन का भविष्यः धार्मिक पहचान और प्रशासनिक उत्कृष्टता के बीच संतुलन आवश्यक

सैय्यद जाहिद अली रियासत

वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर पूरे भारत में व्यापक बहस छिड़ी हुई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही , ये एक चर्चा का विषय है , इस विषय पर मतभेद होना स्वाभाविक हैं, लेकिन यह चर्चा इस बात पर विचार करने का अवसर भी प्रदान करती है कि वक्फ संस्थाओं को किस प्रकार अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सकता है, जबकि उनकी धार्मिक और परोपकारी मूल भावना को भी सुरक्षित रखा जाए। वक्फ इस्लाम की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्था है, जो दान, सामाजिक कल्याण और जनसेवा के सिद्धांतों पर आधारित है। सदियों से वक्फ संपत्तियों के माध्यम से मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों, शैक्षिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। प्रत्येक वक्फ संस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन संपत्तियों का ईमानदारी से प्रबंधन हो और उनका उपयोग दानदाता की इच्छा के अनुरूप समुदाय के हित में किया जाए। इस्लाम न्याय, जवाबदेही और परामर्श (शूरा) पर विशेष बल देता है। पवित्र कुरआन पाक में बार-बार सार्वजनिक मामलों में न्याय और ईमानदारी बनाए रखने की शिक्षा दी गई है। इसलिए, ऐसी किसी भी सुधार प्रक्रिया का मूल्यांकन केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह इस्लामी मूल्यों–पारदर्शिता, न्याय और अमानतदारी–को कितना सुदृढ़ बनाती है। गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के समर्थकों का तर्क है कि कानून, वित्त, शहरी नियोजन, लोक प्रशासन और संपत्ति प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने अनुभव और पेशेवर ज्ञान से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारत में अनेक वक्फ संपत्तियाँ आज भी पूरी तरह उपयोग में नहीं हैं, कई पर अतिक्रमण हो चुका है और कई कानूनी विवादों में उलझी हुई हैं। विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञ अभिलेखों के बेहतर प्रबंधन, कानूनी अनुपालन, डिजिटलीकरण और वक्फ संपत्तियों से आय बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। ऐसी नियुक्तियाँ वक्फ संस्थाओं की कार्यप्रणाली में जनता का विश्वास भी बढ़ा सकती हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया, लेखा-परीक्षण और संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता आने से कुप्रबंधन के आरोप कम हो सकते हैं तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वक्फ का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे। ऐसे समय में जब प्रशासनिक मानकों की लगातार समीक्षा की जा रही है, किसी भी सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्था के लिए विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक हो गई है। साथ ही, यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि वक्फ मूलतः एक इस्लामी संस्था है। इसकी धार्मिक पहचान, उद्देश्य और आध्यात्मिक आधार को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस्लामी न्यायशास्त्र, धार्मिक परंपराओं, मस्जिदों के प्रशासन और वक्फनामों की व्याख्या से संबंधित मामलों का मार्गदर्शन इस्लामी कानून के जानकार योग्य मुस्लिम विद्वानों और विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में वक्फ की विशिष्ट धार्मिक पहचान का सम्मान करते हुए जहाँ आवश्यक हो, वहाँ पेशेवर विशेषज्ञता का समावेश किया जाना चाहिए। भविष्य की दिशा विवादों के बजाय संस्थागत क्षमता निर्माण पर केंद्रित होनी चाहिए। सबसे पहले, देशभर के वक्फ बोर्डों को संपत्ति अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। दूसरा, नियमित वित्तीय लेखा-परीक्षण और स्वतंत्र कार्य-निष्पादन मूल्यांकन को अनिवार्य प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। तीसरा, बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, ताकि वे अपनी कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। इसके अतिरिक्त, वक्फ संस्थाओं को छात्रवृत्तियों, कौशल विकास केंद्रों, स्वास्थ्य परियोजनाओं और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए। वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय का उपयोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अनाथों, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और वंचित परिवारों के कल्याण हेतु। ऐसे प्रयास इस्लामी परंपरा में निहित वक्फ की वास्तविक भावना को साकार कर सकेंगे । भारत की विविधता सदैव उसकी सबसे बड़ी शक्ति रही है। विभिन्न समुदायों के बीच रचनात्मक संवाद और धार्मिक स्वायत्तता के प्रति सम्मान, अधिक सशक्त संस्थाओं और बेहतर प्रशासन का आधार बन सकते हैं। किसी भी वक्फ बोर्ड की सफलता का मूल्यांकन उसके सदस्यों की धार्मिक पहचान से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि वह वक्फ संपत्तियों की कितनी प्रभावी ढंग से रक्षा करता है, दानदाताओं की इच्छाओं का कितना सम्मान करता है और उन लोगों के कल्याण के लिए कितना कार्य करता है, जिनके लिए ये धर्मार्थ संपत्तियाँ स्थापित की गई थीं। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा ध्यान पारदर्शिता, पेशेवर दक्षता और समाज सेवा पर केंद्रित रहना चाहिए। यदि इस्लामी मूल्यों का सम्मान करते हुए और संवेदनशीलता के साथ प्रशासनिक सुधार लागू किए जाएँ, तो वक्फ संस्थाएँ आने वाली पीढ़ियों तक दान, न्याय और सामुदायिक कल्याण के अपने महान उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करती रहेंगी।दूसरा यह कि ऐसे लोगों पर नजर रखना जो वक्फ संपत्तियों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं ,उससे स्वयं लाभ लेते है , ऐसे कुंडली मार कर बैठे लोगों पर सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है ,

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है

X ट्रेंड f

विपक्ष की भूमिका

संसद में विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से नकारात्मक और गैर-जिम्मेदाराना रही है। सत्र शुरू होने के बाद से ही उनका एकमात्र मकसद सदन की कार्यवाही में बाधा डालना रहा है। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है।
- **जगत प्रकाश नड्डा**, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

टेलीकॉम सेक्टर

टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच होने वाला एमओयू ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात है... इस समझौते के ज़रिए देश की कई टेलीकॉम कंपनियाँ मध्य प्रदेश में निवेश करेंगी, जिससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- **डॉ. मोहन यादव**, सीएम, मध्यप्रदेश

युवा आंदोलन

युवा आंदोलन से बड़े मीडिया घरानों के लिए भी एक अहम सबक मिलता है: मुख्यधारा की मीडिया को 'मेन स्ट्रीट मीडिया' बनना होगा। आज संकट सिर्फ़'राष्ट्रीय सरकार' के लिए ही नहीं, बल्कि तथाकथित 'राष्ट्रीय मीडिया' के लिए भी उतना ही बड़ा है।
- **अखिलेश यादव**, सांसद, सपा

फास्ट-ट्रैक कोर्ट

आज सरकार फास्ट-ट्रैक कोर्ट की बात तो करती है, लेकिन 2024 के नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी गई है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 10 सालों में 152 बार पेपर लीक हुए हैं।
- **मल्लिकार्जुन खड़गे**, अध्यक्ष, कांग्रेस

पीओजेके को लेकर भारत ने पाक को लताड़ा

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई निंदनीय, अंतरराष्ट्रीय समुदाय करे जांच

पाक के पीएम के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने जिन 'मुजाहिदीन' को प्रशिक्षित किया, उन्हें धन दिया, हथियार दिए और भारत भेजा, वही अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और पाक के लिए चुनौती बन गए हैं

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

रणधीर जायसवाल

भारत ने शुक्रवार को पाक के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की गतिविधियों की जांच करने तथा उसे इन अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित विदेश मंत्रालय (एमईए) की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके के लोगों के प्रति पाकिस्तान के रवैये का अंदाजा उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को देश का 'दुश्मन' बताया था।

5 जून से अब तक 100 से अधिक मौत, कई घायल और लापता

प्रदर्शनकारियों को 'भारत जैसा दुश्मन' बताया

जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों पर बेहद कठोर कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई में 40 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीओजेके के आम लोगों के प्रति प्रशासन की पूरी बेरुखी तब साफ दिखाई दी, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि वह प्रदर्शनकारियों को 'भारत जैसा दुश्मन' मानते हैं।

40 से अधिक की मौत हुई

जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शनों और लॉन्ग मार्च के दौरान 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जेएएसी सहित कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए गए वीडियो में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कथित सख्ती और कार्रवाई दिखाई गई है। 5 जून से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, कई सौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और सैकड़ों लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से कथित तौर पर गायब कर दिया गया है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा भारत

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस बार ब्रिक्स का अध्यक्ष है और पूरी तैयारी के साथ सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। निमंत्रण और अन्य तकनीकी मामलों पर बाद में जानकारी दी जाएगी। अमेरिकी सीनेट के विधेयक पर उन्होंने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है।

चुनाव शर्मनाक अस्वीकृति साबित हुए

उन्होंने कहा कि कथित चुनाव पाकिस्तान के प्रशासन के लिए एक बड़ी शर्मनाक अस्वीकृति साबित हुए हैं। हिंसक कार्रवाई का सामना कर रहे वहां के लोगों ने गैरकानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मदद मांगी है। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह पाकिस्तान की कार्रवाई की जांच करे और उसे उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएं।

भारत के खिलाफ भेजे गए लोग पाक के लिए चुनौती

जायसवाल ने पाकिस्तान के पीएम के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह की हालिया टिप्पणियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्लाह ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने जिन 'मुजाहिदीन' को प्रशिक्षित किया, उन्हें धन दिया, हथियार दिए और भारत भेजा, वही अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और पाक के लिए चुनौती बन गए हैं।

भारत अंतरराष्ट्रीय प्रकिया का पालन कर रहा: *एमनेस्टी की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के पास रणनीतिक व्यापार नियंत्रण के लिए मजबूत कानूनी और नियामकीय व्यवस्था मौजूद है।*

खबर संक्षेप

19 साल बाद कोलकाता लौटी तस्लीमा नसरीन

कोलकाता। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन शुक्रवार को 19 साल बाद कोलकाता पहुंचीं।

कोलकाता पहुंचने पर तस्लीमा नसरीन बेहद खुश दिखाई दीं। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए अपने देश लौटने जैसा है। मैं खुशी और दर्द दोनों के साथ लौटी हूं। साल 2003 में तस्लीमा नसरीन की किताब द्विखंडित पर पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद साल 2007 में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद तस्लीमा नसरीन को कोलकाता छोड़ना पड़ा था। तस्लीमा नसरीन पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था।

तोतापुरी आमों की हवाई खेप मालदीव पहुंची

नई दिल्ली। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) ने कर्नाटक से

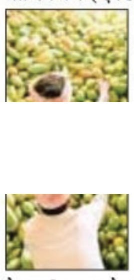

मालदीव के लिए नीलम और तोतापुरी आमों का पहला हवाई परिवहन की सुविधा प्रदान की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि आम निर्यात की यह पहल किसानों को पारंपरिक बाज़ारों की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक लाभ प्रदान करती है। यह निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कर्नाटक की देर से पकने वाली आम की किस्मों को बढ़ावा देने और भारत के आम निर्यात भंडार को और मज़बूत करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

रूस-यूक्रेन जंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

कहा- मारे गए और लापता भारतीयों के परिवारों की हरसंभव मदद करे केंद्र

पहचान के लिए डीएनए सैंपल का मिलान कराएं मुआवजा क्लेम दाखिल करने में सहायता करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश मंत्रालय तुरंत एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो युद्ध में मारे गए, घायल हुए या अब भी लापता भारतीयों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे और उन्हें हर जरूरी जानकारी व सहायता उपलब्ध कराए

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे गए और बाद में युद्ध के मोर्चे पर पहुंचा दिए गए भारतीय नागरिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विदेश मंत्रालय तुरंत एक नोडल अधिकारी

नियुक्त करे, जो युद्ध में मारे गए, घायल हुए या अब भी लापता भारतीयों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे और उन्हें हर जरूरी जानकारी व सहायता उपलब्ध कराए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि पीड़ित परिवार पहले ही भारी मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें समय पर सही जानकारी और हर संभव मदद मिले।

बता दें, यह मामला उन भारतीय युवाओं से जुड़ा है, जिन्हें ट्रैवल एजेंटों ने रूस में अच्छी नौकरी का लालच देकर भेजा था। परिवारों का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद कई युवाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ रूस-यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इस दौरान कई भारतीयों की मौत हो गई, कुछ घायल हुए और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इन्हीं परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार से अपील की थी कि उनके परिजनों का पता लगाया जाए, मृतकों के पार्थिव शरीर भारत लाए जाएं और रूसी सरकार से उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

पीड़ितों को उनकी भाषा में जानकारी दें

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि युद्ध में मारे गए भारतीयों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल का मिलान कराया जाएगा। नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के समक्ष मुआवजा क्लेम दाखिल कराने में विदेश मंत्रालय परिवारों की मदद करेगा। पीड़ित परिवारों को सभी जरूरी जानकारी और प्रक्रियाएं उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता देंगे।

एनएएलएसए करे कानूनी प्रक्रिया में मदद

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे पीड़ित परिवारों की हर कानूनी प्रक्रिया में मदद करें। इसमें मुआवजा क्लेम दाखिल करना, जरूरी दस्तावेज तैयार करना, कागजी कार्रवाई पूरी कराना और पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी से जुड़ी औपचारिकताओं में सहायता शामिल है। अदालत ने कहा कि परिवारों को अनावश्यक कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए।

139 भारतीयों की रिहाई कराई

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि रूसी सेना में मौजूद भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए रूस के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। अब तक 139 भारतीय नागरिकों की रिहाई कराई जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि अभी भी रूसी सेना में बताए जा रहे करीब दो दर्जन भारतीयों की रिहाई के प्रयास जारी हैं। साथ ही लोगों को ऐसे नौकरी के प्रस्तावों से सावधान रहने की सलाह दी गई, जो जोखिम भरे हों और संदिग्ध एजेंसियों द्वारा दिए जाते हों।

यूक्रेन में जहाज पर हमला, 2 भारतीय लापता

रणधीर जायसवाल ने बताया कि 25 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे एमवी एजीएन रैगनर पर हमला हुआ था। जहाज पर चालक दल के सदस्य के रूप में चार भारतीय मौजूद थे। इनमें से दो सुरक्षित हैं, जबकि दो भारतीय अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रोमानिया, दोनों पक्षों की ओर से खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया है। भारत लगातार दोनों देशों के संपर्क में है ताकि लापता भारतीयों के बारे में जानकारी मिल सके। विदेश मंत्रालय उनके परिवारों के संपर्क में भी है और उन्हें हरसंभव सहायता दी जा रही है।

यूक्रेन को दो टूक

भारतीय नाविकों और जहाजों पर हमला अस्वीकार्य

भारत ने काला सागर में व्यापारिक जहाजों और भारतीय

नाविकों पर हो रहे हमलों को लेकर यूक्रेन के सामने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने गुरुवार को यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से फोन पर बातचीत में कहा कि किसी भी पक्ष की ओर से व्यापारिक जहाजों और भारतीय नाविकों पर किए गए हमले बिल्कुल स्वीकार नहीं हैं।

पश्चिम एशिया संघर्ष में 16 भारतीयों की मौत

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि वर्ष 2026 से अब तक 10 भारतीय नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 75 भारतीय घायल हुए हैं। यह जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

नेपाल में सांप्रदायिक तनाव गहराया

सप्तरी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती

- *राष्ट्रपति और पीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की*
- *अब तक हिंसा में 3 लोगों की मौत, 12 से अधिक घायल*

एजेंसी ▶▶ काठमांडू

नेपाल के भारत से सटे तराई क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सुनसरी से शुरू हुई हिंसा अब सप्तरी, धनुषा और सिराहा तक फैल चुकी है। हालात को देखते हुए कई जिलों में कर्फ्यू, निषेधाज्ञा और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

एहतियात के तौर पर सप्तरी जिला प्रशासन कार्यालय ने राजबिराज नगरपालिका के कुछ हिस्सों में शुक्रवार सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया।

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए हिंसा की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

4 जिलों में हालात बेकाबू

सप्ताहांत में सुनसरी में सांप्रदायिक झड़पें शुरू होने के बाद से नेपाल के कई जिलों में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी है, जबकि सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सप्तरी में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद कर्फ्यू वाले जिलों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। ये सभी जिले भारत की सीमा से लगे नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में स्थित हैं। अधिकारी हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक इस हिंसा में 3 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को दो धार्मिक समुदायों के जुलूस और धार्मिक आयोजनों के दौरान हुए विवाद के बाद हालात बिगड़ गए।

पहचान पत्र रखना अनिवार्य

गुरुवार को हिंसा पड़ोसी मधेस प्रांत तक फैल गई, जहां सिराहा जिले में हुई झड़पों में एक किशोर की मौत हो गई। वहीं, सुनसरी हिंसा में घायल एक अन्य व्यक्ति ने कोशी प्रांत में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीमावर्ती सर्लाही जिले की जिला सुरक्षा समिति ने भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसकी जानकारी सहायक मुख्य जिला अधिकारी होम प्रसाद घिमिरे ने दी। एक अलग घटना में गुरुवार रात सिराहा जिले की लहान नगरपालिका में एक अज्ञात हमलावर ने पुलिस कॉन्स्टेबल नारद परियार को गोली मार दी। गोली उनकी दाहिनी जांघ में लगी, जिसके बाद उन्हें विराटनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

युवक की मौत से करदह गांव में पसरा मातम, जांच में जुटी पुलिस

गड़ौरा (महराजगंज)। ठूठीबारी थाना क्षेत्र के करदह गांव में 26 वर्षीय अजय विश्वकर्मा पुत्र रामानंद विश्वकर्मा की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली और मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की। घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रही है। अजय की असामयिक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार वह मिलनसार और सरल स्वभाव के युवक थे। उनकी मौत से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका सुनील कुमार गोयल आ०/पति मोहरी लाल जाति अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला सदर रोड़, शीट नम्बर-11क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4817/23, 3196/4817/24 रकबा 0.01 3/4, 244 एकड़ / वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 29/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका अशोक कुमार अग्रवाल आ०/पति मोहरी लाल अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला सदर रोड़, शीट नम्बर-11क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4817/55, 3196/4817/62 रकबा 418.18, 210 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 29/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

मऊ मानिकपुर के पूर्व विधायक ने देशी हल चलाया

चित्रकूट। मऊ मानिकपुर के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला का एक वीडियो फोटो वायरल रहे जिसमें उन्होंने किसान का देशी हल स्वयं चलाया। पूर्व विधायक आनंद शुक्ला अपने काफिला के साथ पाठा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तभी उनको एक किसान बैल से हल जोतता दिखाई दिया। पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने किसान के पास जाकर हल की मुठिया पकड़ करके खेत जोतने लगे। खेत को देशी हल से जुताई करते हुए विधायक आनंद शुक्ला ने कहा कि प्राकृतिक खेती का अंदाज और मजा अलग ही होता है। उन्होंने कहा जब किसान बैल से खेत जोतता है तो धरती मां भी प्रसन्न होती है तथा अच्छा शुद्ध अन्न भी पैदा होता है। पूर्व मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला लोकप्रिय जुझारु भाजपा के खास नेता हैं। चित्रकूट के कई दिग्गज नेताओं ने मौका परस्ती को देखते हुए दल बदलू नेता के नाम से जाने जाते हैं जो वर्तमान में भाजपा में शामिल हैं।

मेटा की ग्लोबल टीम आएगी भारत

एल्गोरिद्म और कंटेंट मॉडरेशन पर केंद्र सरकार को देगी जवाब

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए लगाए गए प्रतिबंध के मामले में केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब देने अगले सप्ताह मेटा की वैश्विक टीम भारत आ सकती है। कंपनी एल्गोरिद्म और कंटेंट मॉडरेशन पर जवाब देगी।

मेटा इंडिया प्रमुख पर एफआईआर दर्ज

सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी के फर्जी और एआई-जनरेटेड वीडियो वायरल होने के मामले में हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन फर्जी वीडियो को सबसे पहले कहां से और किसने अपलोड किया, इन्हें किन खातों के जरिए आगे बढ़ाया गया और किस इरादे से फैलाया गया।

माइनस 42 डिग्री तापमान में भी नहीं जमेगा तेल

भारतीय सेना और बीपीसीएल ने तैयार किया खास 'एक्सट्रीम वेदर ग्रेड' ईंधन

लॉन्चिंग कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारतीय सेना माइनस 50 डिग्री से लेकर प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में अपने भारी हथियारों और सैन्य साजो-सामान के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करती है। सामान्य डीजल अत्यधिक कम तापमान में जमने लगता है। इसे दूर करने के लिए भारतीय सेना और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने मिलकर ऐसा एक्सट्रीम वेदर ग्रेड (एक्सडब्ल्यूजी) डीजल विकसित किया है, जो -42 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी नहीं जमेगा।

ऑयल का फ्लो बाधित नहीं होगा

सामान्य डीजल में पैराफिन वैक्स मौजूद होता है, जो ईंधन को जरूरी चिकनाई और गाढ़ापन देता है। लेकिन तापमान शून्य से काफी नीचे जाने पर यही वैक्स जमने लगता है और डीजल के फ्लो में बाधा पैदा करता है। इससे ऑयल फिल्टर चॉक हो सकते हैं और गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल विकसित किया है। इसका पोर पॉइंट -42 डिग्री सेल्सियस है, यानी यह इतनी कम तापमान में भी लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा और ऑयल का फ्लो बाधित नहीं होगा।

हूती विद्रोहियों से लाल सागर की समुद्री सुरक्षा होगी

सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने गठबंधन बनाया

एजेंसी ▶▶ रियाद

सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार-विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाब- अल- मनदेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों के सुरक्षा प्रयासों का हिस्सा है।

मुक्त नौवहन, व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति की होगी सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का ऐलान करते सऊदी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी

रेड सी और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में युद्धपोतों की तैनाती की जाएगी

अकेले नहीं जाएंगे मालवाहक जहाज

गठबंधन में शामिल देश अपने युद्धपोत रेड सी और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में तैनात करेंगे। ये जहाज गश्त करेंगे और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करेंगे। तेल टैंक और मालवाहक जहाज अकेले नहीं भेजे जाएंगे। उन्हें काफिले में भेजा जाएगा और साथ में वॉरशिप चलेंगे। युद्धपोतों पर लगे एयर डिफेंस और रडार ड्रोन और मिसाइल हमलों को पहले ही मार गिराने की कोशिश करेंगे। ड्रोन और गश्ती विमान लगातार उड़ान भरेंगे ताकि हूती के लॉन्चिंग पॉइंट का पता चल सके। सभी देश रडार, सैटेलाइट और खुफिया जानकारी आपस में साझा करेंगे।

दुनिया का अहम समुद्री मार्ग है रेड सी

रेड सी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का करीब 30 प्रतिशत समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। इसके आने-जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, बाल अल-मंदेब स्ट्रेट और स्वेज नहर। ईरान जंग के बाद होर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से सऊदी अपना ज्यादातर तेल इसी रास्ते से भेज रहा है।

पंचायत की बैठक के बिना ही बन गया 'फर्जी फौती नामांतरण प्रस्ताव? रजिस्ट्री तक पहुंचा खेल, एफआईआर की मांग से मचा हड़कंप

एसडीएम से लेकर थाना प्रभारी तक पहुंची शिकायत, पूर्व विधायक रामपुकार सिंह भी आए मैदान में; बोले–नहीं हुई कार्रवाई तो होगा बड़ा आंदोलन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

पत्थलगांव। ग्राम पंचायत कछार में कथित फर्जी फौती नामांतरण का मामला अब बड़ा विवाद बनता जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मृतक मीनू चौहान के नाम पर पंचायत का कथित फर्जी प्रस्ताव तैयार कर राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण कराया गया और बाद में उसी आधार पर जमीन की रजिस्ट्री तक कर दी गई। पूरे मामले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) एवं थाना प्रभारी विनीत पांडे से करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

बिना ग्रामसभा, बिना बैठक... फिर कैसे बन गया पंचायत प्रस्ताव?

शिकायत में दावा किया गया है कि ग्राम पंचायत कछार के खसरा नंबर 273/13ख एवं 303/1/ख/1 से संबंधित भूमि के लिए 5 जून 2026 का पंचायत प्रस्ताव दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में उस दिन पंचायत की बैठक ही आयोजित नहीं हुई। आरोप है कि प्रस्ताव पंजी में सरपंच और पंचों के वास्तविक हस्ताक्षर भी नहीं हैं और कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फौती नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई।

नामांतरण के बाद सीधे रजिस्ट्री!

शिकायतकर्ता का आरोप है कि कथित फर्जी प्रस्ताव के आधार पर पहले राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण कराया गया और फिर उसी दस्तावेज के सहारे जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी गई। यदि यह आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ नामांतरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी अभिलेखों में हेरफेर, कूटरचना और जालसाजी जैसे गंभीर अपराधों का रूप ले सकता है।

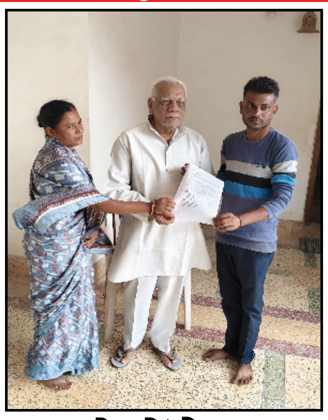

इन लोगों के नाम शिकायत में शामिल

शिकायत में खेमासागर यादव, ग्राम सचिव रामनिवास सूर्यवंशी, पटवारी के.आर. यादव तथा दीपांशु अग्रवाल के नाम का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि यदि जांच में फर्जी दस्तावेज या कूटरचित प्रस्ताव की पुष्टि होती है तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए।

मूल दस्तावेजों की जांच की मांग

पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से ग्राम पंचायत की मूल प्रस्ताव पंजी, बैठक कार्यवाही, सरपंच-सचिव के हस्ताक्षर, राजस्व अभिलेख और अन्य संबंधित दस्तावेजों की फोरेंसिक स्तर पर जांच कराने की मांग की है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

थाना प्रभारी बोले–जांच होगी

थाना प्रभारी विनीत पांडे ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व विधायक रामपुकार सिंह भी आए समर्थन में

मामले ने शनिवार को नया मोड़ ले लिया, जब पीड़ित पक्ष ने पत्थलगांव के पूर्व विधायक रामपुकार सिंह से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पूर्व विधायक ने पीड़ित पक्ष को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे इस पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और शीघ्र ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। मपुकार सिंह ने कहा कि यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे की रणनीति तैयार कर आंदोलन सहित आवश्यक कदम उठाएंगे।

अब प्रशासन की परीक्षा

ग्राम पंचायत कछार के इस कथित फर्जी फौती नामांतरण प्रकरण ने पंचायत और राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाह प्रशासन की जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला क्षेत्र के सबसे चर्चित भूमि विवादों में शामिल हो सकता है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में कैरारिप्पा हाउस ओवरऑल चैंपियन

सैनिक स्कूल में अंतरसदनीय अंग्रेजी वाद–विवाद प्रतियोगिता, कैडेटों ने वक्तृत्व कला का किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कैडेटों के व्यक्तित्व विकास, तार्किक चिंतन, नेतृत्व क्षमता तथा प्रभावी अभिव्यक्ति कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर सदनीय अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय 'एक राष्ट्र-एक चुनावङ रखा गया थाङ। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य कर्नल राजेश बैंदा द्वारा किया गया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाद-विवाद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में तार्किक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता को भी सुदृढ़ बनाती है। प्रतियोगिता का आयोजन जूनियर और सीनियर वर्गों में किया गया, जिसमें सभी सदनों के कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने ज्ञान, आत्मविश्वास और वक्तृत्व कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनावङ विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के समापन पर निर्णायकों द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार कैरारिप्पा हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवर ऑलचैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।

प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग को प्रथम स्थान

कैडेट वंशध पोला (तेजस हाउस) कैडेट लोक श्रुति, कैडेट वंश धपोला, कैरारिप्पा हाउस कैडेट प्रत्यूष दीक्षित, कैडेट माधव शौर्य पाण्डेय रहे।

सोनार समाज राजपुर बेटी के जन्म पर करेगा 1.01 लाख की मदद

मृत्यु में भी सहयोग, बेसहारा बुजुर्गों को मिलेगा 500 रुपये प्रतिमाह

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर।समाज सेवा और आपसी सहयोग की मिसाल पेश करते हुए राजपुर सोनार समाज ने हर वर्ग का दिल जीत लिया है। बेटी के जन्म से लेकर बुजुर्गों की पेंशन और मृत्यु संस्कार तक, हर मौके पर समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। इसी उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के प्रोत्साहन के लिए 'नवीन सर्व सोनार समाज कल्याण समिति, जिला सरगुजा द्वारा रविवार को होटल अलंकार ग्रीन, अंबिकापुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राजपुर से पहुंचे सभी पुरुष, महिला, युवा पदाधिकारियों और वरिष्ठजनों का स्वागत किया गया। सरगुजा सोनार समाज की ओर से इन्हें शाल-श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में राजकुमार सोनी, वरिष्ठजनों में सुरेश कुमार सोनी अध्यक्ष, रामाशीष सोनी

उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश सोनी कोषाध्यक्ष, विकास सोनी प्रमुख सलाहकार, सुनिता सोनी महिला अध्यक्ष, नूतन सोनी महिला महामंत्री सहित पूरी टीम शामिल रही। जिला अध्यक्ष विनोद सोनी के माता-पिता बलदेव सोनी और बेचनी देवी का भी राजपुर समाज के अतिथियों ने भावपूर्ण सम्मान करके आशीर्वाद लिया।

समाज की जनहितैषी योजनाएं चर्चा में

कार्यक्रम में राजपुर समाज के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने समाज द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कन्या विवाह सहायता योजना के तहत प्रत्येक नवजात बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुग्रह पेंशन योजना में बेसहारा बुजुर्गों को 500 रुपये प्रतिमाह, दाह-संस्कार सहायता में लकड़ी, पूजा सामग्री और ब्रह्मभोज में पुरुषों को टोपी वितरण किया जाएगा। हर माह मंदिर में भण्डारा और समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। हर साल भव्य सम्मेलन करके पदाधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। गर्मी में पक्षियों के लिए दाना-पानी, गौ-माता को गुड़ रोटी, कुत्तों को रोटी खिलाने की और वृक्षारोपण करने की अपील की गई।

पदाधिकारियों ने एकता और सेवा पर डाला प्रकाश

कार्यक्रम की शुरूआत अंबिकापुर निवासी स्व. रामलखन सोनी को 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि देकर की गई। इसके बाद गणेश वंदना, सरस्वती वंदन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समाज के पदाधिकारियों रघुनाथ सोनी, विनोद सोनी, प्रकाश सोनी, नीलम सोनी और अरुण सोनी ने समाज में एकता और सेवा के महत्व पर विचार रखे। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला सचिव विजय कुमार सोनी ने किया। उन्होंने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों और मीडिया का आभार व्यक्त किया। समारोह में शिवराम सोनी, अम्बिका सोनी, अशोक सोनी, सुनील सोनी, जयश्री स्वर्णकार, रश्मि स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। राजपुर सोनार समाज की ये पहलें निश्चित ही समाज में सेवा और एकता का नया उदाहरण बन रही हैं।

कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है छत्तीसगढ़ सरकार: मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर - विष्णु देव साय ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों पर किए गए कायराना हमले में सक्ती जिले के निवासी श्री दीपक रात्रे तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निवासी श्री भूपेंद्र भैना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस जघन्य और अमानवीय आतंकी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है और ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, जो परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, वसुंधरा में विद्यालय स्तरीय अनुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट का सफल आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर,- ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, वसुंधरा में विद्यालय स्तरीय अनुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में अनुव्रत समिति की राज्य प्रभारी ममोल कोचेटा उपस्थित रहीं। साथ ही अनुव्रत समिति, अम्बिकापुर की सदस्य प्रतिमा त्रिपाठी जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, वसुंधरा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। विद्यालय समय-समय पर विभिन्न शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन कर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करता है।श्रीमती ममोल कोचेटा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुव्रत आंदोलन के उद्देश्य, उसके मूल सिद्धांतों तथा नैतिक

जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठा, अनुशासन, पारिवारिक एकता एवं मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने तथा अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक संदेश देने के लिए प्रेरित किया।इसके उपरांत अनुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट की छह विधाओं–एकल गायन, समूह गायन, चित्रकला, निबंध लेखन, भाषण तथा कविता प्रस्तुति–का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं का मुख्य विषय ₹हमारा परिवार झ हमारी ताकत₹ रखा गया।प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ भाग लेते हुए अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मक सोच और प्रभावशाली अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी प्रस्तुतियों में परिवार के प्रति प्रेम, आपसी सहयोग, संस्कार, सम्मान, एकता तथा भारतीय पारिवारिक मूल्यों का सजीव चित्रण देखने को मिला, जिसने उपस्थित सभी अतिथियों एवं शिक्षकों को प्रभावित किया। विद्यालय की प्राचार्या बबली अग्रवाल ने विद्यार्थियों के उत्साह एवं प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ बच्चों में नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास, सृजनात्मकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती हैं।

पत्थलगांव के झोंपड़ीनुमा अहाते की अव्यवस्था से लोग परेशान , महंगे दामों पर बिक रहा घटिया क्वालिटी का चखना, सफाई सहित पार्किंग की व्यवस्था भी नही है मौजूद

विभाग बना मूकदर्शक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

पत्थलगांव -- नगर के रायगढ़ रोड़ में स्थित सरकारी शराब दुकान के बगल में बना झोपडीनुमा शासकीय अहाता स्थानीय जनता के साथ पूरे इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है एक ओर जहां न इस अहाते में सफाई की व्यवस्था है और न ही किसी प्रकार के प्रसाधन सुविधा सहित अनेकों समस्या यहां व्याप्त है सबसे बड़ी बात है कि पर्दा ढकने की वजह से अंदर बैठे सुराप्रेमियों की गोपनीयता भंग होती है जिससे यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है जो वर्तमान में अहाता है वह भगवान भरोसे टिका हुआ है । जिससे आने वाले समय मे लोग आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं । जहां ग्राहकों को मिलने वाली अतिरिक्त व्यवस्था की बात क्या की जाए तो छोटे से सामान तक की कीमत आसमान छू रही है है

लेकिन सुविधा के नाम पर ग्राहकों के साथ पूरा ढकोसला किया गया है जिससे आमजन के साथ ग्रामीण भी परेशान हैं यहां तक बिना पहले पैसे दिए कोई भी समान तो क्या एक डिस्पोजल गिलास भी नही दिया जाता । पूरी तरह मनमानी की जाती है जिससे जनता भारी परेशानी को झेलने के लिए मजबूर होती है जिसका सुनने वाला कोई नही । आबकारी सहित प्रशासन को इस दिशा में कोई मतलब होता दिखाई नही दे रहा है ।लेकिन नगर में जनता के सामने लंबे समय से शराब उपभोग करने मशक्कत करनी पड़ती है ।जिस अहाते में नाममात्र की भी सुविधा उपलब्ध नही है । जैसे तैसे लोग मजबूरी में यहां मदिरा का रसपान करने को मजबूर हैं जिनकी ओर ध्यान देने वाला कोई नही है और अव्यवस्था चरम पर है लेकिन इससे प्रशासन को कोई लेना देना नही है जबकि इस आशय की शिकायत उच्चाधिकारियों को कई दफा नागरिकों द्वारा लिखित में भेजी जा चुकी है लेकिन आज तक कार्रवाई अपेक्षित है ।

महंगे दाम एवं घटिया किस्म के बेचे जाते हैं चखना

देखा जाए तो अहाता में किसी भी प्रकार के चखना चौ गुने दाम पर बेचा जा रहा है जिससे ग्राहक परेशान हैं खासकर ग्रामीण ग्राहकों द्वारा ऐसी स्थिति के लिए जब संचालक से विरोध किया जाता है तो उसमें भी ग्राहकों से अभद्रता की जाती है जहां डिस्पोजल गिलास को 5 रुपए की दर से बेच दिया जा रहा है 20 रुपए में 10 रुपए बराबर भी चखना समान नही दिया जाता है ।वहीं यहां बिकने वाले फल सड़े किस्म के होते हैं साथ ही चिकन, मछली फ्रीज मे रखकर दो -तीन दिन पुराने मांस को खुले रूप में बेचा जाता है जबकि यह आहाता नियम के विरुद्ध है जिससे अंदर का वातावरण भी दूषित रहता है लेकिन लोग मजबूरी में यहां बैठने को लाचार हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावे कोई चारा नही है जो परेशानी से कम नही है लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नही दिया गया जो भारी विडंबना है ।

लगातार होता है यातायात बाधित

सड़क के ठीक किनारे में झोंपड़ीनुमा आहाता होने के कारण सभी गाड़ियां इधर उधर खड़ी कर दी जाती है जिससे जगह न होने के कारण यातायात बाधित रहता है जिसमें रायगढ़ रोड़ में स्थित होने की वजह से अक्सर देखा जाता है कि बार बार ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है जिससे ट्रक की लंबी लंबी कतारें लग जाती है जिससे भारी अव्यवस्था फैलती है जो लंबे समय से जारी है जिससे नागरिकों को परेशानी से दो-चार होना पड़ता है लेकिन इस ओर भी ध्यान देने वाला कोई नही है जो समस्या जस की तस बनी हुई है जिससे कई बार इस रोड़ में सड़क हादसे आम बात बन चुका है ।

देखा जाए तो जिस दिन से यहां आहाता खोला गया है जहां अव्यवस्था के अलावे लोगों को सुविधा उपलब्ध नही हो पा रही है जिससे शासन की उक्त व्यवस्था से सुराप्रेमियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।वहीं कार्रवाई न होने से लोग विरोध का मन बना रहे हैं अब देखना है कि कई शिकायतों के बाद आबकारी विभाग और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है यह देखने वाली बात है ।

प्रयास विद्यालय में माहवारी स्वच्छता एवं तनाव प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। संकल्प हेल्थ फाउंडेशन एवं संकल्प हॉस्पिटल, अंबिकापुर के संयुक्त तत्वावधान में जिले के विभिन्न विद्यालयों में संचालित माहवारी स्वच्छता जागरूकता अभियान अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय, घंघरी में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 किशोरियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकिता गोयल ने किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता, संतुलित पोषण एवं पेरिनियल हाइजीन के महत्व की जानकारी दी।उन्होंने सैनिटरी पैड का समय-समय पर परिवर्तन, साफ एवं सूती अंतःवस्त्रों का उपयोग, पर्याप्त पानी पीने तथा संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सही स्वच्छता एवं पौष्टिक आहार अपनाकर कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव संभव है। प्रयास विद्यालय की छात्राएं नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए डॉ. गोयल ने तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, पर्याप्त नींद, योग एवं नियमित अध्ययन के महत्व पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन एवं चिकित्सकीय अनुभव साझा करते हुए छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम दौरान छात्राओं ने माहवारी, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका डॉ. गोयल ने सरल एवं वैज्ञानिक ढंग से समाधान किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ओमप्रकाश साहू ने संकल्प हेल्थ फाउंडेशन एवं संकल्प हॉस्पिटल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, ऐसे जागरूकता कार्यक्रम किशोरियों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

बैगलेस डे पर स्कूलों में महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों की लगी प्रदर्शनी

छात्रों ने पेंटिंग व चित्रकारी के माध्यम से शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीदो के परिजन एवं पूर्व सैनिक हुए शामिल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शनिवार को बैगलेस डे पर जिले के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन तथा जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती लता बेक एवं जिला मिशन समन्वयक मनोज कुमार साहू के निर्देश पर समस्त शालाओं में महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों तथा देश और समाज को अपना योगदान देने वाली महत्वपूर्ण हस्तियों की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर छात्रों ने स्वयं पेंटिंग, स्क्रैच एवं चित्रकारी के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्रीय एकता एवं समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हर कोई देश और समाज के लिए अपना योगदान दे सकता है।

प्रतापपुर विकासखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरहरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू परमानंद कोसरिया के पुत्र कमलेश कोसरिया एवं सीमा पर लड़ चुके भूतपूर्व सैनिक शिवचरण नापित उपस्थित हुए, वहीं विकासखंड सूरजपुर के माध्यमिक शाला रुनियाडीह में शहीद परिवार के पौत्र अंकित कोसरिया शामिल हुए। दोनों ही विद्यालय परिवारों ने अतिथियों का अभिनंदन किया। मुख्य वक्ता के रूप में शहीद परिजनों ने बताया कि गोकुल प्रसाद जी वर्ष 1925 में दुर्ग से उदयपुर आए और महाराजा साहब के कहने पर सूरजपुर प्रस्थान किया। हरिद्वार में आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद वे वंदे मातरम आंदोलन से प्रारंभ से ही जुड़ गए थे तथा हैदराबाद में आयोजित आंदोलन में भाग लेने के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जहां प्रताड़ना सहते हुए 1 अप्रैल 1939 को उनकी शहादत हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय संस्कार विकसित होंगे। भैयाथान विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल गंगोटी में अधिवक्ता अनिल गोयल, पूर्व एसडीओ जल संसाधन एस.के. तिवारी, सेवानिवृत्त शिक्षक रविशंकर मिश्रा, समाजसेवी लालचंद अग्रवाल एवं सहायक संचालक शिक्षा ने छात्रों के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। बालक माध्यमिक शाला रामानुजनगर में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय साहू, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं गोयल एवं जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा ने विद्यार्थियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्रों से संवाद स्थापित करते हुए अपनी सफलता की कहानी साझा की, जिससे बच्चे प्रेरित हुए और उन्होंने अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बारी-बारी से बताया।

विद्यालयों में छात्रों द्वारा बनाई गई महापुरुषों की चित्रकारी की प्रतियोगिता आयोजित कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही स्कूलों में पोषण वाटिका का विस्तार एवं न्योता भोजन का भी आयोजन किया गया। जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा ने बताया कि बैगलेस डे स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के निर्देश पर प्रत्येक शनिवार आयोजित होने वाला सतत कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से छात्रों को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों, समाजसेवियों, सफल व्यक्तियों, एसएमसी सदस्यों एवं पालकों को स्कूलों से जोड़कर बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम में सहायक संचालक शिक्षा अजय सिंह, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं संकुल समन्वयकों ने विद्यालयों में उपस्थित होकर अपना योगदान दिया।

किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य, शांति एवं सुरक्षा हेतु कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जिले को सुरक्षित व अपराध मुक्त बनाने के सामूहिक प्रयासों में करें सहयोग की अपील

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य को लेकर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रेना जमील ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जारी आदेश के अनुसार अब जिले में किसी भी मकान, भवन, दुकान या अन्य परिसर को किराये पर देने से पहले संबंधित किरायेदार का पूर्ण विवरण एवं सत्यापन निकटतम थाना या चौकी में देना अनिवार्य होगा। बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को किराये पर आवास या भवन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही होटल, लॉज, ढाबों तथा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण भी संबंधित थाना में उपलब्ध कराना होगा। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने यह निर्णय जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधों की रोकथाम तथा संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित

करने के उद्देश्य से लिया है। कई बार किरायेदारों का सत्यापन नहीं होने के कारण अपराधी तत्व अपनी पहचान छिपाकर वारदातों को अंजाम देते हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आदेश के तहत मकान मालिकों को किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान-पत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज कर संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। यदि कोई किरायेदार अथवा उसके यहां आने वाला व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त दिखाई देता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देना भी आवश्यक होगा। होटल संचालकों को भी संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचानी होगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनहित, शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों तक अथवा अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

सत्यापन समाज और परिवार की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम-एसपी

पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से अपील की है कि किरायेदारों का सत्यापन केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज और परिवार की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक मकान मालिक, होटल संचालक एवं संस्थान प्रमुख इस आदेश का पालन करते हुए पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सूरजपुर को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अपराधमुक्त बनाने के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिल सके।

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 20 लोगो ने किया रक्तदान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर में शनिवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्काउट-गाइड सदस्यों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं ने मानव सेवा का संदेश देते हुए अधिक से अधिक लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका शर्मा ने सभी रक्तदाताओं का स्वागत करते हुए उनके इस मानवीय कार्य की सराहना की।उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि एक यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचा सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करने का आह्वान किया। शिविर में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, स्काउट एवं गाइड के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। रक्तदान करने वालों में डॉ. प्रियंका शर्मा, आयुष चिकित्सक डॉ. सीमा त्रिपाठी, राजेश द्विवेदी,

ऋषि दूबे, अभिषेक उपाध्याय, स्काउट मास्टर योगेश साहू, संदीप तिवारी, श्रीकांत पांडेय, विवेक शुक्ला, संजू गुप्ता, रघुनाथ जायसवाल, शिवम दूबे सहित अनेक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिविर में 20 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में जिला चिकित्सालय सूरजपुर से आई टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम में डॉ. यशोदा मिर्धा, अशोक सिंह, शालिनी गुर्जर, अंजली साहू एवं जय सिंह ने रक्त संग्रहण एवं शिविर संचालन में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

व्यवस्था की आड़ में संलग्नीकरण, डीईओ ने जारी किया सख्त आदेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। संलग्नीकरण पर शासन की रोक के बावजूद शिक्षा विभाग में व्यवस्था के नाम पर कर्मचारियों से अन्य कार्यालयों में कार्य कराए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती लता बेक ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कर्मचारी अपनी मूल पदस्थ संस्था से अलग किसी जिला अथवा अन्य कार्यालय में व्यवस्था के तहत कार्य नहीं करेगा। इस सबसे अधिक शिकायतें सूरजपुर और रामानुजनगर को लेकर सामने आ रही थीं, जहां संलग्नीकरण समाप्त होने के बाद भी कुछ गैर शैक्षणिक कर्मचारियों से व्यवस्था के नाम पर कार्य कराए जाने के आरोप लग रहे थे। शिकायतों में कहा गया कि कुछ लिपिक अपनी मूल संस्था में केवल उपस्थिति दर्ज कर पूरे दिन बीईओ कार्यालय में कार्य करते थे। इससे उनकी मूल संस्थाओं का कार्यालयीन कार्य प्रभावित होने की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं। लगातार सामने आ रही इन्हीं शिकायतों के बाद जिला

शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए व्यवस्था की इस प्रणाली पर रोक लगाने के उद्देश्य से सख्त आदेश जारी किया है।

आदेश में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पूर्व निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का संलग्नीकरण पहले ही समाप्त किया जा चुका है तथा उन्हें अपनी मूल पदस्थ संस्था अथवा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर वहीं से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद यदि कोई कर्मचारी अन्य कार्यालय में कार्य करता पाया जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत कदाचार माना जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए तथा 3 अगस्त से प्रत्येक कर्मचारी अपनी मूल पदस्थ संस्था अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्वीकृति के 10 महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ काम, 90 फीसदी सोलर प्लांट बंद, अंधेरे में 38 गांव

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। सुदूर पहाड़ी अंचल चांदनी बिहारपुर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों के 38 से अधिक गांव आज तक नियमित विद्युत सुविधा से वंचित हैं। लगभग दस वर्ष पहले ग्रामीणों को रोशनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सोलर पावर प्लांट एवं सोलर होम लाइट सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन नियमित रखरखाव और तकनीकी देखरेख के अभाव में अब पूरी व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र के करीब 90 प्रतिशत सोलर पावर प्लांट पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जबकि शेष प्लांट भी खराब होने की कगार पर हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले क्षेत्र में नियुक्त तकनीशियन समय-समय पर बैटरियों में डिस्टिल्ड वाटर डालने, इन्वर्टर और कंट्रोल पैनल की मरम्मत करने तथा छोटी-बड़ी तकनीकी खराबियों को तत्काल दूर कर देते थे। इससे सोलर व्यवस्था किसी तरह संचालित रहती थी। लेकिन तकनीशियनों को कार्यमुक्त किए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में रखरखाव व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। अब छोटी खराबी भी कई दिनों तक ठीक नहीं होती और कई सोलर पावर प्लांट महीनों से बंद पड़े हैं। बरसात के मौसम में शॉर्ट सर्किट, बैटरी खराब होना, इन्वर्टर फेल होना और अन्य तकनीकी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अभिलेखों में मरम्मत और रखरखाव का दावा किया जाता है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है।ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 10 महीने पहले क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों में विद्युत विस्तार कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें कोल्हुआ, महुली, चोगा, करौटी, खैरा, कछिया, कछवारी, नवडीहा, बाक और असुरा ग्राम पंचायतें शामिल हैं। लेकिन स्वीकृति मिलने के बावजूद आज तक न बिजली के खंभे लगाए गए और न ही लाइन विस्तार का कार्य शुरू किया गया। इससे हजारों ग्रामीणों की उम्मीदें अधूरी रह गई हैं।

टाइगर रिजर्व से लगे गांवों में अंधेरा बना खतरा

क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व से लगी हुई हैं। कोल्हुआ, महुली, चोगा, करौटी, खैरा, कछिया, कछवारी, नवडीहा, बसनारा, मोहरसोप, बैजनपाठ, लुल्ह, भूण्डा, तेलाईपाठ, रसौंकी, उमझर, जूड़वनिया और रामगढ़ सहित कई गांव सीधे जंगल की सीमा से सटे हैं। यहां आए दिन हाथी, भालू, बाघ, लकड़बग्घा सहित अन्य वन्यजीव गांवों तक पहुंच जाते हैं। शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। बिजली और सोलर व्यवस्था ठप होने के कारण ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। जंगली जानवरों के साथ-साथ सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों का खतरा भी बना रहता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, महिलाएं और बुजुर्ग असुरक्षित महसूस करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र की बिजली और सोलर पावर प्लांट की समस्या को लेकर कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतों में बंद पड़े सोलर पावर प्लांटों की मरम्मत, तकनीशियनों की पुनर्नियुक्ति तथा विद्युत विस्तार कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की गई। लेकिन शिकायतों के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि कई मामलों में कागजों में शिकायतों का निराकरण दिखा दिया जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। तीन दर्जन से अधिक गांवों में सोलर व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। कई स्थानों पर सोलर होम लाइट वर्षों से बंद पड़ी हैं, जबकि कई सोलर पावर प्लांट केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बंद पड़े सभी सोलर पावर प्लांटों का विशेष सर्वे कराकर तत्काल मरम्मत कराने, नियमित रखरखाव, स्वीकृत 11 ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण कार्य को तत्काल शुरू कराये जाने की मांग की है।

16 को पहुंचेगी लाइफलाइन एक्सप्रेस, विभिन्न रोगों की होगी नि:शुल्क जांच एवं सर्जरी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के नागरिकों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की 256वीं लाइफलाइन एक्सप्रेस विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर 16 अगस्त से 5 सितंबर तक नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी संचालित होगी तथा आवश्यकतानुसार मरीजों की नि:शुल्क जांच एवं सर्जरी भी की जाएगी।शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद सर्जरी, कान की जांच एवं सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी कटे-फटे होंठ एवं जलने के बाद संकुचन, दांतों की जांच एवं उपचार तथा महिलाओं के लिए स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच एवं स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि केवल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मुड़े हुए हाथ-पैर की जांच एवं सर्जरी नि:शुल्क की जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार आंखों की ओपीडी 16 से 21 अगस्त तथा

सर्जरी 17 से 22 अगस्त तक, कान की ओपीडी 22 से 27 अगस्त तथा सर्जरी 23 से 28 अगस्त तक होगी।

वहीं मुड़े हुए हाथ-पैर एवं प्लास्टिक सर्जरी की ओपीडी 28 से 31 अगस्त तथा सर्जरी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक की जाएगी। दांतों की जांच एवं उपचार 1 से 5 सितंबर तक होगा। महिलाओं के स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच एवं स्क्रीनिंग 16 से 21 अगस्त तक की जाएगी।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा लाइफलाइन एक्सप्रेस के सफल संचालन एवं अधिक से अधिक जरूरतमंद मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, मितानिन, सखी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पात्र मरीजों की पहचान कर उनका लाइफलाइन एक्सप्रेस में पंजीयन कराने तथा उपचार के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरतमंद नागरिकों को इस नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा का अधिकतम लाभ मिल सके।

जिला प्रशासन ने आग्रह किया है कि अवसर का लाभ उठाते हुए आवश्यकता अनुसार अपना पंजीयन कराएं तथा अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को भी इस नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर की जानकारी दें। शिविर में आने वाले मरीज अपने साथ आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी या अन्य वैध पहचान पत्र अवश्य लाएं। भर्ती मरीजों के साथ केवल एक सहयोगी को ही रहने की अनुमति होगी।

रामानुजनगर में सामु. स्वा. केंद्र भवन हेतु मिली 2.50करोड़ की स्वीकृति

विधायक भूलन बोले- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना प्राथमिकता

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के रामानुजनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने रामानुजनगर में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण के लिए 2.50 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को भविष्य में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। बताया गया है कि लंबे समय से रामानुजनगर क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए विधायक भूलन सिंह मरावी द्वारा शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उनके प्रयासों के बाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान के अंतर्गत नए अस्पताल भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की है।

स्वीकृत राशि से बनने वाला नया अस्पताल भवन आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसके निर्माण के बाद मरीजों के लिए बेहतर उपचार व्यवस्था, जांच सुविधाओं का विस्तार, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा अस्पताल के आधारभूत ढांचे में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे रामानुजनगर सहित आसपास की अनेक ग्राम पंचायतों के लोगों को उपचार के लिए दूरस्थ अस्पतालों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। विधायक भूलन सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की जनता को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने विश्वास जताया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ऐसे प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

स्मार्ट मीटर के नाम पर मची लूट, बिल देखकर उड़ रहा उपभोक्ताओं का होश

एआईसीसी के सदस्य ने कांग्रेस के प्रदेशव्यापी आंदोलन को लेकर की पत्रकारों से चर्चा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक अगस्त से प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन का मुख्य मुद्दा महंगी बिजली, बढ़े हुए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर है।

इसी क्रम में शहर के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, राजीव भवन में प्रेस से चर्चा करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने कहा कि यह आंदोलन लगातार 2 महीने तक चलेगा। कांग्रेस की 3 मुख्य मांगों में बिजली के दाम में की गई बढ़ोतरी को वापस लेना, उपभोक्ताओं को जबरन थोपे गए स्मार्ट मीटर को वापस लेना और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई 400 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ योजना को फिर से शुरू करना है। उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा से अवगत कराते हुए बताया कि एक अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पदाधिकारियों की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता आयोजित कर सरकार की नीतियों का विरोध करने के बाद 2 अगस्त से कांग्रेस के कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने के खिलाफ आवेदन फॉर्म भरवाएंगे। उपभोक्ताओं से बढ़े बिल के खिलाफ विरोध पत्र भी भरवाए जाएंगे। दो महीने बाद सभी जिले से एकत्रित आवेदन के साथ सभी जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव करके एकत्र किए गए आवेदन जमा किए जाएंगे और इसकी पावती ली जाएगी। अंतिम चरण में सभी जिलों की पावती लेकर रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में सभी बूथ, पंचायत, मंडल, ब्लॉक, जिला कमेटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, डॉ. जेपी श्रीवास्तव, शफी अहमद, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता, हेमन्त तिवारी, अरविंद सिंह गप्पू, इंद्रजीत सिंह धंजल, अनूप मेहता, मदन जायसवाल, आलोक सिंह, विनय शर्मा बंटी, आशीष वर्मा सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

बिजली बिल हॉफ योजना से भी किया वंचित

आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने बताया कि, भाजपा सरकार ने जुलाई माह में घरेलू उपभोक्ताओं के दाम में 30 से 50 पैसे और गैर घरेलू में 20 से 40 पैसे, कृषि में 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। सरकार बनने के बाद 5वीं बार दाम बढ़े हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने केवल 2 पैसे बढ़ाए थे और 400 यूनिट तक बिल हॉफ योजना भी लागू की थी। भाजपा ने बिजली बिल हॉफ योजना से तो उपभोक्ताओं को वंचित किया ही है, स्मार्ट मीटर लगाकर इस्टीमेट से ज्यादा बिल भेजा जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा है।

निजी कंपनी को लाभ, उपभोक्ताओं पर बोझ

एआईसीसी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने कहा कि, निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाए बिजली बिल का बोझ लादने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के शासनकाल में 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ योजना के बाद भी विद्युत उत्पादन निगम लाभ में था। इधर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अभी तक के कार्यकाल में पांच बार बिजली का दाम बढ़ाया है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जिस प्रकार स्मार्ट मीटर लगाने की बाध्यता को सरकार ने समाप्त किया, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को मुक्त किया जाना चाहिए।

पालने से 5 माह की बच्ची को उठाकर ले गया 'बंदर'

पानी से भरे ड्रम में डालने से घबराए स्वजन, बच्ची का चल रहा उपचार

छ.ग.फ्रंटलाइन लखनपुर। थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरी कला में शुक्रवार 31 जुलाई की शाम करीब 4 बजे एक बंदर ने बस्ती में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। बंदर ने घर के पालने में सो रही 5 माह की मासूम बच्ची को उठाकर पानी से भरे ड्रम में फेंक दिया।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को अचानक एक बंदर गांव में पहुंच गया। पहले तो उसे लोग कौतूहलवश देख रहे थे, लेकिन उसके उत्पात को देखकर लोग घरों में दुबक गए। इसी दौरान बंदर एक घर में घुसा और पालने में सो रही त्रिशिका प्रजापति पिता सुदर्शन प्रजापति 5 माह, निवासी रजपुरी कला को उठाकर आंगन में रखे पानी से भरे नीले ड्रम में डालकर भाग गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर दौड़ते-भागते ड्रम के पास पहुंचे, और आनन-फानन में ड्रम से बाहर निकाल कर लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था। खबर लिखे जाने तक बच्ची का इलाज जारी है।

इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जंगली बंदर बस्ती में घुसकर उत्पात मचाने लगते हैं, लेकिन इस बार बच्ची की जान आफत में पड़ गई।

उत्पाती बंदरों पर नजर रखने की जरूरत

घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से उत्पाती बंदरों की निगरानी के साथ इन्हें पकड़ने वाली टीम को सक्रिय करने का आग्रह किया है। वहीं जागरूक लोगों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, घरों के दरवाजे को बंद रखने, छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने की अपील की है। वन विभाग को भी ऐसी सूचनाओं को तत्काल संज्ञान में लेना होगा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न होने पाए।

'बैगलेस डे' पर शहीद के स्वजन और भूतपूर्व सैनिक का सम्मान

रंगोली-पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन, अतिथियों ने की सराहना

छ.ग.फ्रंटलाइन सरहरी/प्रतापपुर। कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा सूरजपुर के निर्देशानुसार शनिवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरहरी में 'बैगलेस डे' को देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को समर्पित कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाला विकास समिति की अध्यक्ष एवं सरपंच मीनमती ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सूरजपुर जिले के शहीद बाबू परमानंद के पुत्र कमलेश कोसरिया उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों में उपसरपंच उषा देवी, जनपद सदस्य कुंती शिवपाल कुशवाहा, भूतपूर्व सैनिक शिवचरण नापित और विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस.एस. ध्रुवे शामिल रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी, छत्तीसगढ़ महतारी और सरगुजा संभाग के 40 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। राज्य गीत अरपा पैरी के धार के गायन के साथ आयोजन शुरू हुआ। मुख्य अतिथि कमलेश कोसरिया को विद्यालय परिवार ने साल-श्रीफल देकर सम्मानित किया। अपने भावुक उद्बोधन में उन्होंने बताया कि उनके बड़े पिता ने महज 18 साल की उम्र में वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने के जुर्म में देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने बच्चों को देशभक्ति का संदेश दिया। भूतपूर्व सैनिक शिवचरण नापित ने सीमा पर देश की रक्षा के अपने संस्मरण साझा कर विद्यार्थियों में जोश भरा। कक्षा 12वीं के पंकज कश्यप और कक्षा 11वीं के अंकित कुमार ने देशभक्ति भाषण दिए। बीईओ एमएस ध्रुव ने अपने प्रेरक उद्बोधन से बच्चों का मार्गदर्शन किया।

रंगोली और पोस्टर प्रदर्शनी में दिखी प्रतिभा

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण देशभक्ति आधारित रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता रही। निर्णायक मंडल में निशा तिवारी, विजय भारती और मनीषा एक्का थे। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम कक्षा 11वीं से उषा, अनुष्का, गंगोत्री, सविता पैकरा, द्वितीय कक्षा 12वीं से पंकज, सूरज, सुमित, मयंक एवं कक्षा 9वीं से सृष्टि, छाया, साक्षी, तृतीय कक्षा 11वीं से हाफ्रिजा, जीवित कुमारी रहे। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम प्राची यादव कक्षा 11वीं, द्वितीय पूर्ति सिंह कक्षा 10वीं, तृतीय पार्वती कक्षा 10वीं रहे।

एकता की शपथ और पौधारोपण-कार्यक्रम संयोजक एवं साहित्यकार अजय कमार चतुर्वेदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भावना और पौधारोपण की शपथ दिलाई। सभी ने संकल्प लिया कि जिस तरह एक पेड़ बिना भेदभाव छांव देता है, उसी तरह वे भी प्रेम और भाईचारे से रहेंगे। इसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सामूहिक पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार चतुर्वेदी और अविनाश तिवारी ने, आभार प्रदर्शन विजय भारती ने किया। प्राचार्य दिलीप तिवारी' ने कहा कि कार्यक्रम ने बच्चों को देशभक्ति और राष्ट्रीयता से गहराई से जोड़ने का काम किया।

ग्रामसभा में पंचायत सचिव से मारपीट का प्रयास, केस दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन रामानुजनगर। विशेष ग्रामसभा में प्रक्रिया का हवाला देकर राशनकार्ड के लिए हस्ताक्षर नहीं करने पर शासकीय कार्य में बाधक बनते हुए पंचायत सचिव से गालीगलौज और कॉलर पकड़कर मारपीट के लिए उतारू होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

सूरजपुर जिला के रामानुजनगर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरेश्वरपुर के सचिव भुनेश्वर सिंह ने पुलिस को बताया है कि, 31 जुलाई को पंचायत भवन में कार्यालय कलेक्टर पंचायत शाखा के आदेशानुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान पंचायत भवन में अनावेदक अभिषेक मानिकपुरी पिता बिजेन्द्र मानिकपुरी ने कल्पना दास पति राकेश दास का राशन कार्ड बनाने के लिए हस्ताक्षर करने जबरन दबाव बनाया। पंचायत सचिव ने जब नियमानुसार राशन कार्ड का जांच करके आगे की कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय में भेजने की बात कही तो अभिषेक कालर पकड़कर गाली-गलौज और मारपीट करने उतारू हो गया। इस दौरान विशेष ग्रामसभा में उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध बीएनएस की धारा 296, 351(3), 221, 132 का अपराध दर्ज किया है।

पढ़ाई में बाधा न बने धुंधली नजर, पहाड़ी कोरवा बच्चों के बीच पहुंचे नेत्र सहायक

शंकरगढ़ के दूरस्थ इलाके में स्वस्थ आंखों की रोशनी से खिलेगा आश्रम के बच्चों का भविष्य

छ.ग.फ्रंटलाइन शंकरगढ़। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का अभियान जारी है। इसी कड़ी में विकासखंड शंकरगढ़ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी कोरवा आश्रम, भोदना में 31 जुलाई को स्कूल नेत्र जांच शिविर आयोजित करके 'अंधेरा नहीं उजाला चाहिए, हर बच्चे को स्वस्थ नजर चाहिए' संदेश दिया गया। शिविर में नेत्र सहायक अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने आश्रम में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की आंखों की जांच की। जांच के दौरान बच्चों को आंखों को स्वस्थ रखने, बीमारियों से बचाव और समय पर उपचार से फायदे जैसी जानकारी दी गई।

मोतियाबिंद बनी आम बीमारी

नेत्र सहायक का कहना है कि, यदि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से गांव के अंतिम छोर तक हो, तो हर नागरिक स्वास्थ्य लाभ पा सकता है। इस योजना को धरातल के अंतिम छोर तक ले जाने के लिए जिला अंधत्व कार्यक्रम के अंतर्गत बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ विकासखंड अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग करने में लगा है। आज की व्यस्त जीवनशैली में मोतियाबिंद सबसे आम बीमारी है। समय पर ऑपरेशन से दृष्टि वापस लौटाई जा सकती है।

समस्याओं के ये हैं प्रमुख कारक

मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के लगातार उपयोग से आंखों में जलन, धुंधलापन, चुभन और दर्द जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए बलरामपुर जिले के सभी स्कूलों और आश्रमों में चरणबद्ध तरीके से बच्चों का नेत्र जांच करने की रणनीति बनाई गई है, ताकि कोई भी बच्चा दृष्टि की समस्या के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। जांच से समय रहते बच्चों के आंखों में किसी प्रकार की दृष्टि बाधा तो नहीं है, इसका भी पता चलेगा।

ऐसे करें आंखों का तनाव कम

नेत्र सहायक दुर्गेश त्रिपाठी ने सलाह दी है कि, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाप के बढ़ते उपयोग को देखते हुए बच्चों और युवाओं को 20-20-20 के नियम को ग्राह्य करना होगा। स्क्रीन पर लगातार 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। पढ़ाई और मोबाइल के बीच हर 20 मिनट में ब्रेक लें, इससे आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकता है और आंखों को स्वस्थ रखा जा सकता है। शिविर में आंखों को अनमोल बताते हुए नियमित जांच और साफ-सफाई पर जोर दिया गया। बच्चों को हाथ धोने, धूल से बचाव और पौष्टिक आहार लेने की जानकारी भी दी गई। मोतियाबिंद के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने कहा गया। तेज धूप में काला चश्मा और धूल से बचाव के लिए साफ पानी से आंखें धोना चाहिए।

आजीवन कारावास की सजा से दंडित कैदी की इलाज दौरान मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक को दो दिन पहले ही बीमार हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जानकारी के मुताबिक, कोरिया जिला के सोनहत थाना अंतर्गत ग्राम कटगोड़ी निवासी रामकेश्वर साहू पिता शोभनाथ साहू 37 साल को वर्ष 2021 में पत्नि की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया था। न्यायालय ने 25 जुलाई 2022 को उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। इसके बाद सजायाफ्ता कैदी को बैकुंठपुर उपजेल से 01 अगस्त 2022 को स्थानांतरित करके केंद्रीय जेल अंबिकापुर में निरूद्ध किया गया था। 29 जुलाई को पेट में दर्द और पेशाब में जलन की शिकायत पर जेल चिकित्सक की सलाह पर उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां इलाज के दौरान एक अगस्त को तड़के 4.15 बजे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। जेल प्रशासन ने मृतक के शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

के.आर. टेक्निकल कॉलेज में 5 दिवसीय एफडीपी संपन्न, कुलपति ने पोर्टल का शुभारंभ किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। के.आर. टेक्निकल कॉलेज, संजय नगर में एआई इंटीग्रेशन इन क्लास रूम टीचिंग विषय पर आयोजित पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुक्रवार को समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर के कुलपति डॉ. राजेन्द्र लाकपाले थे।

कुलपति ने इस अवसर पर महाविद्यालय द्वारा विकसित एलएमएस पोर्टल और एआई पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों एवं रिसोर्स पर्सन को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया। समापन उद्बोधन में डॉ. लाकपाले ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। यदि हम नई तकनीकों को नहीं अपनाएंगे तो शैक्षिक परिवेश में पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि एआई कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती, बल्कि एक दक्ष शिक्षक को और अधिक प्रभावी बनाती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे एआई का उपयोग कक्षा शिक्षण को रोचक और दृश्यात्मक बनाने के लिए करें, लेकिन साथ ही इसकी नैतिकता और सीमाओं को भी समझें। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान शिक्षकों के शिक्षण और शोध कार्यों को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाएगा।

एआई का उपयोग समय की आवश्यकता

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के उपाध्यक्ष राहुल जैन ने कहा कि के.आर. टेक्निकल कॉलेज गुणवत्तापूर्ण और तकनीक-सक्षम शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डायरेक्टर डॉ. रीनू जैन ने कहा कि आधुनिक शिक्षा में एआई का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग समय की आवश्यकता है। प्राचार्य डॉ. रितेश वर्मा ने बताया कि नए एलएमएस और एआई पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन शिक्षण, मूल्यांकन और डिजिटल संसाधन एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। एआई पोर्टल से शिक्षक पाठ योजना, प्रश्न-पत्र और प्रेजेंटेशन बनाने में मदद ले सकेंगे।

मिला सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण

27 से 31 जुलाई तक चले इस कार्यक्रम में शिक्षकों को एआई के मूल सिद्धांत, एआई आधारित पाठ योजना, प्रश्न-पत्र निर्माण, गूगल एआई स्टूडियो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, संस्थागत एआई नीति और डेटा गोपनीयता जैसे विषयों पर सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम दिन प्रतिभागियों ने मोबाइल और लैपटॉप पर स्वयं डिजिटल कंटेंट तैयार किया। इस एफडीपी का आयोजन आईक्यूएसी और कंप्यूटर विज्ञान विभाग द्वारा एसजीजीयू के कंप्यूटर विज्ञान विभाग तथा छत्तीसगढ़ सोसायटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का संचालन एनएस कार्यक्रम अधिकारी विनितेश गुप्ता ने किया। इस दौरान डॉ. एच.एस. होता, डॉ. रेशम लाल प्रधान, डॉ. एच.एस.पी. टोंडे सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित थे।

नाबालिगों द्वारा वाहन चालन पर रोक के लिए शैक्षणिक संस्थानों पर पुलिस की नजर

विशेष जागरूकता अभियान के साथ विद्यार्थियों, प्राचार्यों से हो रहे रूबरू

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सड़कों पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में सरगुजा पुलिस द्वारा जिले भर में अंडरएज ड्राइविंग के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सड़क दुर्घटनाओं से बचाना है। शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना, चौकी एवं यातायात पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

स्कूलों में पहुंचकर दी गई समझाइश

अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा मल्टीपरपस स्कूल एवं डी हिलॉक्स स्कूल में छात्र-छात्राओं को एकत्रित करके यातायात नियमों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बिना हेलमेट के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। साथ ही छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए अधिकृत स्कूल वाहन अथवा स्वजन के साथ आने की समझाइश दी गई।

प्राचार्यों को दिए निर्देश

जिले के समस्त विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रधान पाठकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले छात्र-छात्राओं को दोपहिया वाहन से विद्यालय आने की अनुमति न दें। यदि कोई छात्र-छात्रा वाहन चलाते पाया जाता है तो पहले उसे समझाइश दी जाए। अभियान के दौरान वाहन के साथ पाए गए छात्रों से ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट के संबंध में पूछताछ की गई।

काउंसलिंग और वैधानिक कार्रवाई

पुलिस द्वारा जागरूकता के साथ-साथ सख्ती भी बरती जाएगी। नाबालिग छात्र-छात्राओं के वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उनके अभिभावकों को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। समझाइश के बाद भी सुधार न होने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चलानी कार्रवाई एवं अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सरगुजा पुलिस की अपील

सरगुजा पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है, वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने के लिए नहीं दें। यह अभियान आगामी दिनों में भी जिले के विभिन्न स्कूलों में लगातार जारी रहेगा।

कीटनाशक का सेवन किए युवक की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के प्रतापपुर थाना अंतर्गत ग्राम टुकुडांड निवासी नानसाय पिता धनराम गोड़ 40 वर्ष ने अज्ञात कारणों से 25 जुलाई को कीटनाशक का सेवन कर लिया। प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र से रिफर करने पर स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराए थे। यहां इलाज के दौरान शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात दो बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर